twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | बुधवार, 30 जुलाई, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 254, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

दुनिया के किसी नेता ने जंग नहीं रुकवाई: मोदी

आज आतंक के आकाओं को डर सताता है कि भारत आएगा और मार कर जाएगा: मोदी

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों पर आतंक के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और बताया कि उनकी सरकार ने भारत की विदेश और रक्षा नीति में पिछले 11 सालों के दौरान बड़े बदलाव कर देश को सशक्त बनाया है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि आतंकवाद पर दुनिया के देशों से समर्थन मिला लेकिन कांग्रेस से समर्थन नहीं मिला। साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से आज आतंक के आकाओं को डर सताता है कि भारत आएगा और मार कर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के दावे का खंडन किया और विपक्ष पर कटाक्ष किया कि उनके नेता ह्यबयान बहादुरोंह्ल की तरह केवल सवाल उठाते हैं। वे आतंकी हमले पर की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं और हमला होने पर यह सवाल उठाते हैं कि कार्रवाई को क्यों रोका गया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस से जुड़ी विदेश नीति और आतंक के खिलाफ रणनीति दोनों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टिकरण की राजनीति के कारण आतंक के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की गई। यहां तक कि वोट बैंक की राजनीति के कारण 26/11 के हमले को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, देश हैरान है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। वे कह रहे हैं कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से थे। हमें इसका सबूत दीजिए। पाकिस्तान भी वही मांग कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है।

पाकिस्तान के एयर बेस आईसीयू में पड़े हुए है: मोदी

पीएम ने कहा कि उन्हें डर सताता है कि भारत आएगा और मार कर जाएगा। यह आज का न्यू नॉर्मल सेट किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से हमले की आशंका थी। इसीलिए वह न्यूक्लियर हमले की भी धमकियां दे रहा था। भारत ने जैसा सोच वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा और आज भी उसके एयर बेस आईसीयू में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया ने देखा कि हमारी कार्रवाई का कोई दायरा नहीं है। हम सिंधु से लेकर सिंदूर तक जा सकते हैं।

कांग्रेस ने तुष्टिकरण और वोट बैंक के लिए 'भगवा आतंक' की बात की: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर आतंक के प्रति नरम रूख अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि इसका कारण तुष्टीकरण की राजनीति रही है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते कठोर कानूनों को कमजोर करने की कोशिश की गई। आतंकी हमलों को हिन्दू आतंक से जोड़ने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जारी पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में आज भाग लिया। कांग्रेस के पास कभी राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन नहीं था। और आज पार्टी इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कई जानें गँवानी पड़ीं, हमें अपनों को खोना पड़ा। आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती थी।

हमारी सरकार ने 11 सालों में ये कर दिखाया है। कांग्रेस के राज में आतंकवाद के फैलने का एक बड़ा कारण उनकी तुष्टिकरण की राजनीति रही है। उन्होंने कहा, जब देश पर मुंबई में 26/11 का बड़ा आतंकी हमला हुआ, तो हमने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ज़िंदा भी पकड़ा। दुनिया ने इसे स्वीकार किया, पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस 'भगवा आतंकवाद' की थ्योरी को आगे बढ़ाने में लगी रही। वे हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनके (कांग्रेस) के एक नेता ने तो एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक से यहाँ

ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के हथियारों का दुनिया में डंका बजा दिया: मोदी

प्रधानमंत्री ने इस दौरान रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का जिक्र किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के हथियारों का दुनिया में डंका बजा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई विजन नहीं था। उनके कालखंड में छोटे-छोटे हथियार के लिए भी विदेशों पर निर्भरता थी। उनकी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव किये जिससे आज भारत का रक्षा उत्पादन ढाई सौ प्रतिशत और निर्यात 30 गुना बड़ा है और भारत के हथियार दुनिया के 100 देशों तक पहुंच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए उन्होंने सदन को बताया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को अपने ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का देश है और हम समृद्धि और शांति चाहते हैं पर यह नहीं भूलना चाहिए की समृद्धि और शांति का मार्ग शक्ति से होकर जाता है। प्रधानमंत्री कहा कि कांग्रेस ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हमेशा समझौता किया है। आज उसके नेता पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को वापस क्यों नहीं लिया। वह पूछना चाहते हैं कि आखिर पीओके पर कब्जा किसकी सरकार ने होने दिया। उन्होंने कहा कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार के गलत निर्णय की कीमत आज भी भारत चुका रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आतंक के खिलाफ कार्रवाई से आज आतंकियों के मन में दहशत का माहौल है। उन्होंने कहा कि हमले के बाद अब उनकी आंखों में नींद नहीं आती।

सरकार ने निर्यात और आयात में तेजी लाने के लिए कई पहल कीं: पंकज चौधरी

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) फ्रेमवर्क के अंतर्गत निर्यात और आयात को तेज करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने सदन को बताया कि भारत सरकार के उठाए गए प्रमुख कदमों में एईओ प्रमाणपत्र धारकों के सुविधा के लिए किए गए निम्नलिखित काम में खेपों के आयात और निर्यात में उच्च स्तर की सुविधा, सीधे बंदरगाह पर डिलीवरी (डीपीडी) वाले आयात कंटेनरों और/या निर्यात कंटेनरों के लिए सीधे बंदरगाह पर प्रवेश (डीपीई) की सुविधा, कुछ प्रकार की खेपों के लिए स्वचालित निकासी और ऑन-साइट जांच, टियर-क्क्क्र और टियर-क्क्र एईओ प्रमाणपत्र धारकों के लिए देर से भुगतान की सुविधा, जहां भी लागू हो, बैंक गारंटी जमा करने के मानदंडों में ढील और भागीदार सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों से मान्यता शामिल हैं।

पंकज चौधरी ने सदन को बताया कि एईओ प्रमाणपत्र धारकों को उन विदेशी सीमा शुल्क प्रशासनों से व्यापार सुविधा सहायता भी मिलती है, जिनके साथ भारत ने पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उनकी वैश्विक व्यापार दक्षता में बढ़ोतरी होती है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 30 जून, 2025 तक 5,892 एईओ प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

भारत अब शांति की कीमत चुकाने में नहीं, वसूलने में विश्वास रखता है : जितेन्द्र सिंह

नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शांति की कीमत चुकाने में नहीं बल्कि शांतिभंग करने वालों से कीमत वसूलने में विश्वास रखता है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 'एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत' कार्यक्रम का बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

न्यूक्लियर स्टेट के नाम पर धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत: एनडीए सांसद

नई दिल्ली

राज्यसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय झा ने कहा कि इसकी सफलता देश ने ही नहीं, दुनिया ने भी स्वीकारी है। हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को पोषित कर रहा है। उन्होंने जापान गए प्रतिनिधिमंडल के अ?ुभव साझा करते हुए कहा कि कैसे सभी ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारत अपनी रक्षा में कदम उठा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को बता दिया है कि यह पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है। हम घर में घुस कर मारते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह भी साफ बता दिया है कि अगर देश में कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो वो अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। हमने दुनिया को बता दिया है कि खून औ? पानी एक साथ नहीं बह सकता। न्यूक्लियर स्टेट के नाम पर धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अब एक शोध का विषय है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार से देश और दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने ऑल पार्टी डेलिगेशन ने एकजुट हो कर अपनी बात रखी।

भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा: राजनाथ

नई दिल्ली

राज्यसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट के तीन आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया है। भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी सेनाओं और अन्य सुरक्षा बलों की भूमिका की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जाएगा। आज का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इस ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना

और यह स्पष्ट संदेश देना था कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरूआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलू का गहराई से अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे। लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें, आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे लेकिन पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई क्षति न पहुंचे।

राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल रुका है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, अगर पाकिस्तान फिर कोई दुस्साहस करता है तो इसे पुनः शुरू करने में हिचकिचाएंगे नहीं। भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, सुरक्षा बलों को लक्ष्य चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अपनी संप्रभुता और आत्म-सम्मान की रक्षा करना जानता है और आतंकवाद के खिलाफ वह किसी भी हद तक जा सकता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके ठीक नहीं किया, तो उन्हें जनता को बताना चाहिए कि उनके पास इसका विकल्प क्या है?

सारे आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान और पाकिस्तान कांग्रेस की भूल: अमित शाह

नई दिल्ली

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और पाकिस्तान के प्रति नरम नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सारे आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस की भूल है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल से लोकसभा में जारी पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में भाग लिया। उन्होंने ऑपरेशन महादेव, पहलगाम हमले पर एनआईए जांच, पूरे घटनाक्रम और आंतकवाद के खिलाफ भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से अवगत कराया। उन्होंने कांग्रेस सरकारों के दौरान कथित तौर पर की गयी ऐतिहासिक गलतियों का भी उल्लेख किया और तुष्टीकरण के मुद्दे पर पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही देश के विभाजन को स्वीकार किया। पीओके को हासिल किए बिना 1948 में संघर्ष विराम और 1971 में मिली बड़ी जीत के बावजूद पीओके नहीं लेना पार्टी की बड़ी भूल रही। अगर ऐसा न किया होता तो न रहता बांस न बजती बांसूरी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान कांग्रेस की भूल है। अगर उन्होंने बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता, तो आज पाकिस्तान नहीं होता। शाह ने विपक्ष के पहलगाम हमले के बाद निर्णायक बढ़त हासिल करने के बावजूद भी आगे कार्रवाई नहीं करने के सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आतंक के खिलाफ कार्रवाई था न कि युद्ध लड़ना। युद्ध का अपना परिणाम होता है। इसी सदंर्भ में उन्होंने कांग्रेस नेताओं को 1971 के युद्ध की याद दिलाई। उन्होंने कहा, 1971 में 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया।

पहलगाम अटैक करने वाले तीनों आतंकी मारे गए

नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को धर्म पूछ कर 26 सैलानियों की नृशंस हत्या करने वाले तीनों आतंकवादी सोमवार को एक संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिन्दूर पर सोमवार से जारी चर्चा में भाग लेते हुए सदन और देश के साथ यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, मैं सदन के माध्यम से कल हुए ऑपरेशन महादेव की जानकारी पूरे देश को देना चाहता हूं। कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान, अफगान और

हमजा जिब्रान नाम के तीन आतंकवादी सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में मारे गए। गृहमंत्री ने कहा कि सुलेमान, लश्कर ए तैयबा का ए श्रेणी का कमांडर था। पहलगाम और गगनगीर आतंकी हमले में वो लिप्त था, इसके बहुत सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास हैं। अफगान और हमजा जिब्रान भी ए ग्रेड के आतंकवादी थे जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा थे। 22 मई को सेंसर के माध्यम से आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। फिर हमारी 4 पैरा के नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने एक साथ आतंकवादियों को घेर लिया। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा था, उनमें ये तीनों आतंकवादी शामिल थे और कल तीनों ही मारे गए।

रिजर्व बैंक ने एआईएफ योजना में बैंक के निवेश की सीमा 10 फीसदी तय की

मुंबई/नई दिल्ली

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मंगलवार को नए नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन (एनबीएफसी) सहित किसी एकल विनियमित संस्था (आरई) द्वारा वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) योजना में निवेश करने की सीमा को कोष के 10 फीसदी तक तय की है। ये नियम 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। आरबीआई ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि बैंक और अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में कैसे निवेश कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक (एआईएफ में निवेश) निर्देश, 2025 के मुताबिक किसी भी एआईएफ योजना में सभी विनियमित संस्थाओं का कुल योगदान उस योजना के कोष के 20 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

हरियाणा में शुरू होगी लाडो सखी योजना और डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम: सीएम सैनी

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण हरियाणा में अग्निशमन केंद्रों की आवश्यकता का आंकलन किया जाए ताकि आवश्यकतानुसार नए फायर स्टेशनों की स्थापना सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 से अब तक की गई सभी घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित घोषणाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय

निवासियों को सडक, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भले ही किसी क्षेत्र में एक ही घर हो, संबंधित विभाग वहां मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि किसी भी निवासी को असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी विभाग को शहरी स्थानीय निकाय विभाग और गौ सेवा आयोग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर दो माह के भीतर बेसहारा गोवंश को सडकों और सार्वजनिक स्थलों से हटाकर गौशालाओं में संरक्षित किया जा सके। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कलेसर क्षेत्र से यमुना नदी के जल को चैनल के माध्यम से पंचकूला सहित अन्य स्थानों तक लाने के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए।

'ऑपरेशन महादेव' के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, तीन आतंकी ढेर,मारा गया पहलगाम हमले में शामिल मूसा सुलेमानी

एजेंसी

श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर के लिडवास इलाके में सोमवार को सुरक्षाबलों को आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सेना के जवानों ने 'ऑपरेशन महादेव' के तहत तीन आतंकियों को मार गिराया गया है। यह मुठभेड़ लिडवास में हुई, जहां सेना ने आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें मार गिराया। ऑपरेशन के संबंध में सेना की चिनार कॉर्प्स ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा की। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ऑपरेशन महादेव- लिडवास इलाके में आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ है और ऑपरेशन जारी है।

इसके कुछ समय बाद एक अन्य पोस्ट में चिनार कॉर्प्स ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना के अधिकारियों के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर लिडवास इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जो कई घंटों तक चली। मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षाबलों को सफलता मिली। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। 'ऑपरेशन महादेव' को हाल के समय में घाटी में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है। यह ऑपरेशन इस बात का संकेत है कि सेना और अन्य सुरक्षाबल आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी मुस्तैदी और सटीक रणनीति के साथ जुटे हुए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन मैदान में पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के बाद से आतंकवाद-रोधी अभियान आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और मानव खुफिया जानकारी का उपयोग कर रहे हैं।

पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए सशस्त्र बलों को खुली छूट दे दी। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचे पर लक्षित हमले किए और नौ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया।

यह मुठभेड़ लिडवास में हुई, जहां सेना ने आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें मार गिराया। ऑपरेशन के संबंध में सेना की चिनार कॉर्प्स ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा की।

सुप्रीम कोर्ट में 'श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन अध्यादेश 2025' को चुनौती, सुप्रीम करेंगे सुनवाई बेंच का फैसला

एजेंसी

नई दिल्ली । मथुरा के वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति ने यूपी सरकार के अध्यादेश 'श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025' को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीजेआई अब यह तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में बताया गया कि इससे जुड़ी एक और याचिका दूसरी बेंच में लंबित है। इसके चलते कोर्ट ने मामले को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष भेजने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई अब यह तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी। दरअसल, श्री बांके बिहारी मंदिर के वर्तमान प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश सरकार के 'श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025' की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस अध्यादेश के तहत मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण एक नवगठित ट्रस्ट को सौंपा गया है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने मंदिर के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है। याचिका में कहा गया है कि यह मंदिर के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के समान है। मंदिर राज्य की संपत्ति या ट्रस्ट नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि श्री बांके बिहारी मंदिर एक निजी धार्मिक संस्थान है, जो स्वामी हरिदास के वंशजों और लगभग 360 सेवायतों द्वारा संचालित होता रहा है। 1939 में बनाई गई प्रबंधन योजना के तहत मंदिर का संचालन होता है, जिसका यह अध्यादेश उल्लंघन करता है। इस प्रबंधन अधिग्रहण को इलाहाबाद हाई में भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राज्य द्वारा प्रबंधन और नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया।

कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामला: मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली । मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर सर्वोच्च अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंत्री विजय शाह की मंशा पर अदालत को शक है। शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि क्या विजय शाह ने अब तक अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। कोर्ट ने एसआईटी (विशेष जांच टीम) से पूछा कि आखिर विजय शाह के बयान से जिन लोगों की भावनाएं आहत हुईं, उनके बयान अब तक क्यों नहीं लिए गए? एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और वायरल वीडियो क्लिप की जांच भी की जा चुकी है। एसआईटी ने कहा कि वह फिलहाल सभी रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है और जांच रिपोर्ट को 13 अगस्त तक अंतिम रूप दिया जाएगा। एसआईटी के इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस मामले में कोर्ट अब 18 अगस्त को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसआईटी के एक सदस्य को स्टेटस रिपोर्ट के साथ 18 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। बता दें कि इंदौर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था। शाह ने कर्नल कुरैशी की ओर इशारा करते हुए कहा था, जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी अपनी बहन को भेजा। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद मंत्री कुंवर विजय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक मिनट 13 सेकंड का वीडियो जारी कर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपनी विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी थी।

महाराष्ट्र के पुणे में धर्म परिवर्तन करा रहे अमेरिकन नागरिक सहित तीन गिरफ्तार

मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे जिला स्थित पिंपरी चिंचवड़ में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले अमेरिकन नागरिक सहित तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिंपरी पुलिस स्टेशन की टीम इस मामले की गहन छानबीन कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिंपरी कैंप स्थित वैष्णो देवी मंदिर के पास रहने वाले शिकायतकर्ता सनी बंसीलाल दानानी (27) की शिकायत के आधार पर पिंपरी पुलिस ने धर्म परिवर्तन के प्रयास का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसे कहा गया था कि अगर तुम ईसा मसीह को भगवान मानोगे, तो तुम्हें सुख, शांति, धन और मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। बाकी सभी भगवान और धर्म सिर्फ़ कहानियाँ हैं। इसके अलावा, धर्म परिवर्तन करने पर भविष्य में आर्थिक मदद का वादा करके उनकी धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया गया।

'भारत ने किसी के दबाव में नहीं रोका ऑपरेशन सिंदूर'

राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों पर दिया जवाब

एजेंसी

नई दिल्ली । ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम कि भारत ने किसी दबाव में आकर ऑपरेशन को रोका, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सरासर गलत है कि भारत ने किसी बाहरी दबाव के चलते सैन्य कार्रवाई रोकी। राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बयान देते हुए कहा कि भारत ने वे सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए थे, जो इस ऑपरेशन के तहत तय किए गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य युद्ध छेड़ना नहीं, बल्कि पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकी कैंपों को नष्ट करना था, जिन्हें वर्षों से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा था। हमारी सेनाओं ने केवल उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया, जो सीधे तौर पर भारत में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे। 'रक्षा मंत्री ने बताया कि 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की एक अहम एयरफील्ड पर निर्णायक हमला किया। इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने हार मानते हुए भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) से संपर्क कर कार्रवाई रोकने की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया और कहा, 'अब रोकिए।' इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संवाद हुआ और हमने यह तय किया कि ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा, लेकिन यह ऑपरेशन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से दोबारा कोई हरकत हुई, तो ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की यह पराजय केवल सैन्य रूप से नहीं, बल्कि उसके मनोबल की भी हार थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों के अद्वितीय शौर्य को 140 करोड़ देशवासियों ने देखा और गर्व महसूस किया। रक्षा मंत्री ने कहा, 'मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हमारे सैनिकों का मनोबल बुलंदी पर था। वे न केवल भारतीय सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्वाभिमान की भी रक्षा कर रहे हैं।'

कर्नाटक : एक साल में 981 किसानों ने की आत्महत्या

एजेंसी

बेंगलुरु । कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024 से जुलाई 2025 के बीच राज्य में 981 किसानों ने आत्महत्या की। 1 साल 4 महीने के वक्त में इतनी खुदकुशी किसानों की दयनीय स्थिति को उजागर करती है। यह स्थिति राज्य में कृषि संकट और अपर्याप्त समर्थन की गंभीर तस्वीर पेश करती है। हवेरी जिला इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां 128 किसानों ने आत्महत्या की। इसके बाद मैसूरु (73), धारवाड़ (72), और बेलगावी (71) का नंबर आता है। वहीं, बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, उडुपी, और कोलार जिलों में कोई भी किसान आत्महत्या दर्ज नहीं हुई। अन्य जिलों में हासन (47), बीदर (45), शिवमोग्गा (45), गदग (44), यदगिर (43), दावणगेरे (42), चिक्कमगलूरु (39), मांड्या (39), बागलकोट (35), चित्रदुर्गा (34), विजयपुरा (27), रायचूर (25), कोप्पल (25), तुमकुरु (17), उत्तर कन्नड़ (14), दक्षिण कन्नड़ (1), कोडगु (1), बल्लारी (1), और चामराजनगर (1) में आत्महत्याएं दर्ज की गई।सरकार ने 807 प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया है, लेकिन 18 मामलों में राहत अभी भी लंबित है। किसानों की आत्महत्या के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कर्ज का बोझ, फसल की विफलता, कम आय, और बाजार तक पहुंच की कमी। कर्नाटक में बार-बार सूखा, अनियमित बारिश, और महंगे कृषि निवेश ने किसानों को आर्थिक तंगी में धकेल दिया है।

हालांकि सरकार ने समय-समय पर कर्ज माफी, बीज और उर्वरक सब्सिडी दी है। सरकार की ओर से गठित समितियों और राहत पैकेज के बावजूद, आत्महत्याओं की संख्या में कमी नहीं आ रही है। किसान संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि किसानों को उचित फसल मूल्य, ऋण राहत और बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाएं।

'ऑपरेशन सिंदूर' पर चिदंबरम ने उठाए सवाल, एनडीए सांसद बोले 'संसद में दिया जाएगा जवाब'

एजेंसी

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के पहलगाम हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान को सत्तारूढ़ दल ने 'सबसे बड़ा झूठ' करार दिया है। एनडीए सांसदों का कहना है कि देश को सैन्य कार्रवाई पर गर्व है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब संसद में दिया जाएगा। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, 'भारत सरकार को 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर गर्व है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब संसद में दिया जाएगा। जब भी पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है, विपक्ष में कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं। गलवान संकट के बीच भी चीनी राजदूत संग रात्रि भोज करते हैं। वहीं, चिदंबरम को बाहर बयानबाजी करने की बजाय लोकसभा में अपनी बात रखनी चाहिए, जहां उनके हर सवाल का जवाब मिलेगा। विपक्ष चुनाव हारने के बाद बहाने ढूंढ रहा है। दरअसल, चिदंबरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार से सबूत मांगे थे। वहीं, इंडिया गठबंधन की ओर से सांसद महुआ माजी ने इस चर्चा की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए और पक्ष-विपक्ष दोनों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। गठबंधन इस चर्चा का स्वागत करता है और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। संसद में खुली चर्चा से सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।राज्यसभा सांसद मयंक भाई नायक ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक बताया और कहा कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार संसद में हर सवाल का जवाब देगी।

बीजेपी सांसद सी.पी. जोशी ने चिदंबरम पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले आतंकी हमलों का कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। मोदी सरकार ने पहली बार दुश्मन देश में घुसकर आतंकवादियों को खत्म किया, जैसा कि पुलवामा और पहलगाम के हमलों के जवाब में देखा गया। क्या उन्होंने कभी आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश की? वहीं, सांसद अरुण गोविल ने विपक्ष के बयानों को 'सबसे बड़ा झूठ' करार दिया और कहा कि संसद में 'ऑपरेशन सिंदूर' के साथ-साथ नारी सम्मान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है और जनता इसे देख रही है।

प्रधानमंत्री से मिले नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, हिमाचल की आपदा पर मांगी एरिया स्पेसिफिक राहत

शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए भारी नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने हालिया आपदा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि इस आपदा में न केवल लोगों के घर तबाह हुए, बल्कि कई जगहों पर जमीनें भी बह गईं, जिससे प्रभावितों के पास पुनः घर बनाने के लिए भी स्थान नहीं बचा है। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए 'वन संरक्षण कानून' में रियायत दी जाए ताकि उन्हें सुरक्षित स्थलों पर बसाया जा सके। जयराम ठाकुर ने हिमाचल के भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को 'एरिया स्पेसिफिक' राहत पैकेज देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लक्षित मदद से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्निर्माण संभव हो सकेगा। ठाकुर ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा से राज्य में कुल 1200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जिसमें केवल सराज विधानसभा क्षेत्र में ही 1000 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति आंकी गई है। गौरतलब है कि बीते 30 जून की रात सराज, करसोग और नाचन क्षेत्र में कुल 42 लोगों की जान गई, जिनमें 29 मौतें अकेले सराज से हुई हैं। 500 से अधिक घर पूरी तरह बह गए और 1000 घर क्षतिग्रस्त हुए जो अब रहने योग्य नहीं हैं। वहीं मण्डी जिला के ही धर्मपुर के स्याठी गांव के पूरी तरह जमींदोज हो जाने से वहां के लोग अब भी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं।जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से प्रदेश में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन कराने का भी आग्रह किया।

'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट में 30 जुलाई को होगी सुनवाई

एजेंसी

नई दिल्ली । राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। कोर्ट को बताया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म में कुछ बदलावों के बाद इसे दोबारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट लेने को कहा है। कोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया में समय लगेगा इसलिए फिल्म की रिलीज अभी टाल दी गई है।फिल्म के निर्माता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कोर्ट में कहा कि मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार फिल्म में छह कट लगाए गए हैं और डिस्क्लेमर में भी बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले सीबीएफसी ने फिल्म को 55 कट के साथ मंजूरी दी थी, लेकिन अब नए बदलावों के बाद दोबारा सर्टिफिकेशन की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है और सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद ही फिल्म रिलीज हो सकती है।

बिहार में एनआईआर के जरिए वोटिंग का अधिकार छीनने की साजिश : खड़गे

एजेंसी

नई दिल्ली । बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। सोमवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद परिसर में जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित इंडी अलायंस के कई बड़े नेता और सांसद शामिल हुए।यह विरोध-प्रदर्शन संसद के मकर द्वार के पास आयोजित किया गया, जहां विपक्षी नेता एक बड़ा बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बैनर पर लिखा था- 'एसआईआर- अटैक ऑन डेमोक्रेसी'। यानी एसआईआर लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। केंद्र सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एकतरफा और पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। विपक्षी सांसदों ने यह भी मांग की कि एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा कराई जाए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए खड़गे ने पोस्ट में लिखा, संसद में इंडी गठबंधन जनता के अधिकारों की आवाज उठाता रहेगा। पूरे देश में एसआईआर लागू करवाकर एक साजिश के तहत कमजोर वर्गों से वोटिंग का अधिकार छीनना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र और संविधान पर हम आरएसएस-भाजपा की मनुवादी मानसिकता हावी नहीं होने देंगे।

उल्लेखनीय है कि एसआईआर को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए एक वैध और जरूरी कदम है। आयोग के हलफनामे के अनुसार, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 1.5 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंटों को शामिल किया गया था।

मंत्री कपिल मिश्रा ने सादतपुर में पीएनजी गैस पाइप लाइन कार्य का किया शुभारंभ

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के सादतपुर में पीएनजी सुविधा के लिए गैस पाइप लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया द्य मंत्री कपिल मिश्रा ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को भी यहां सुना। कपिल मिश्रा ने यहां क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाएगा। पीएनजी आपूर्ति की सुविधा से लोगों का पैसा भी बचेगा और सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। सादतपुर क्षेत्र के के, एल, एम, एन ब्लॉक में पाइप लाइन बिछाने के कार्य चार महीने में पूरा कर लिया जाएगा और 6 महीने में पीएनजी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर तक पीएनजी आपूर्ति पहुंचाने का निर्णय लिया है। इस दिशा में सादतपुर के के, एल, एम और एन ब्लॉकों एवं सादतपुर एक्सटेंशन के बी. ब्लाक से पीएनजी सुविधा हेतु पाइप लाइन बिछाने हेतु कार्य आज से शुरू किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही यह पीएनजी सुविधा करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के सोनिया विहार एवं सोनिया विहार एक्सटेंशन, सभापुर, खजूरी खास, बिहारीपुर, शेरपुर, तुकमीरपुर, सादतपुर के ए से लेकर एफ तक सभी ब्लॉक, मिलन गार्डन, दयालपुर ई एवं एफ ब्लॉक, श्रीराम कॉलोनी, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, मुकुंद विहार, वेस्ट करावल नगर, अंकुर एन्क्लेव, वेस्ट कमल विहार और चांद बाग तक विस्तारित की जाएगी।

करोल बाग में दंपति ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटके मिले शव

नई दिल्ली। मध्य जिले के करोल बाग क्षेत्र में रविवार देर रात गली नंबर 44 स्थित एक मकान में एक दंपति ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटना की जानकारी पीसीआर कॉल के माध्यम से मिली। जिसमें बताया गया कि पति-पत्नी दोनों ने फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौक पर पहुंची। पुलिस अधिकारी के अनुसार मकान संख्या 4841, तीसरी मंजिल पर पति-पत्नी के शव सीलिंग फैन से लटके पाए गए। मौके पर तुरंत क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है। जांच में मृतकों की पहचान पति देबू भौमिक (36) और पत्नी मल्लिका भौमिक (32) के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे।पुलिस अधिकारी के अनुसार यह दंपति पिछले 4 महीने से करोल बाग के उक्त पते पर किराए पर रह रहे थे। देबू भौमिक सोने के आभूषण बनाने का काम करता था। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक दंपति की एक 7 वर्षीय बेटी भी है, जिसे उन्होंने पश्चिम बंगाल स्थित अपने पैतृक गांव में छोड़ा हुआ था।

झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए करोडों का बजट, पात्रों को मकान देने की व्यवस्था : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए करोड़ों रुपये का बजट निर्धारित किया है। अगर किसी वजह से झुग्गियों को हटाया जा रहा है तो पात्र झुग्गी वालों को मकान देने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने रविवार सुबह शालीमार बाग स्थित फाटक वाली झुग्गी कैंप का दौरा करते हुए यह बातें कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बस्ती को हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस जारी किया है, क्योंकि यह झुग्गी बस्ती उसकी जमीन पर बसी हुई है। रेल विभाग आजादपुर रेलवे स्टेशन का विस्तार कर रहा है। मुख्यमत्री ने कहा कि इस झुग्गी बस्ती को हटाने को लेकर वर्ष 2020 में सर्वे किया गया था, उस वक्त की आम आदमी पार्टी सरकार ने न कोई निर्णय लिया और न ही रेलवे से बात की। लेकिन हम लोग आपके लिए योजना बनाने में लग गए, ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों पर संकट आया तो मैं आपसे मिलने आ गई, क्योंकि दिल्ली सरकार बेवजह झुग्गियों को हटाने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजधानी में विकास कार्यों को गति देने या अन्य वजहों से अगर झुग्गियों को हटाया जाएगा तो सरकार पात्र लोगों के पुनर्वास का रास्ता खोलेगी, ताकि वे भी दिल्ली के विकास से जुड़ सकें।

दस हजार रुपये के लिए कर दी नौकर की हत्या, शव सेप्टिक टैंक से बरामद

नई दिल्ली। दक्षिण जिले के मेहरौली इलाके स्थित फार्महाउस के सेप्टिक टैंक से एक शव बरामद हुआ। जांच में पता चला जिसका शव बरामद हुआ है वह बीते शनिवार से लापता था। जांच में मृतक की पहचान 42 वर्षीय सीताराम के रूप में हुई है। वह पिछले 10 वर्षों से उक्त फार्महाउस में केयरटेकर के रूप में कार्यरत था। दक्षिण जिले के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि घटना का खुलासा तब हुआ जब 26 जुलाई की सुबह फार्महाउस के अन्य स्टाफ ने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला है और सीताराम गायब है। मालिक दिल्ली से बाहर थे। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलने पर थाना मेहरौली में गुमशुदगी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तलाश शुरू की और फार्महाउस परिसर की गहन जांच की गई।

शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' का परीक्षण, 475 किमी. दूर था निशाना

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत ने सोमवार को सुबह 9:35 बजे ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की परीक्षण रेंज 475 किलोमीटर तक थी। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 500 किमी. तक है। इस मिसाइल को पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर तैनात किये जाने की मंजूरी सरकार से मिल चुकी है। मिसाइल की जद में पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेस और महत्वपूर्ण चीनी ठिकाने आएंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल 'प्रलय' का उड़ान परीक्षण ओडिशा तट के कलाम द्वीप से किया। बैलिस्टिक मिसाइल ने 475 किलोमीटर तक की रेंज में अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। इस दौरान कई उपकरणों के

जरिए तट रेखा से इसके प्रक्षेपण की निगरानी की गई। मिसाइल ने उच्च डिग्री की सटीकता के साथ निर्दिष्ट लक्ष्य को निशाना बनाया। मिसाइल की सभी उप-प्रणालियों ने भी संतोषजनक प्रदर्शन किया। सभी सेंसर ने मिसाइल प्रक्षेपवक्र को ट्रैक करके सभी घटनाओं को कैप्चर किया। मिसाइल को उच्च-स्तरीय दुश्मन ठिकानों, जैसे हवाई अड्डे, आपूर्ति डिपो और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की मारक क्षमता को बड़ा बढ़ावा देते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तैनाती के लिए 'प्रलय' बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दे दी है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनाती करने के लिए यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल 150-500 किलोमीटर के बीच लक्ष्य को मार सकती है।मिसाइल में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 500-1000 किलोग्राम का भार वहन करने में सक्षम है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी तैनाती का उद्देश्य पश्चिमी (पाकिस्तान) और उत्तरी (चीन) दोनों सीमाओं पर विश्वसनीय प्रतिरोध और त्वरित पारंपरिक प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

साइबर ठगी में 3.81 करोड़ की हेराफेरी, सीबीआई ने तीन आरोपितों को किया गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर 3.81 करोड़ रुपये की साइबर ठगी में शामिल होने का आरोप है। मुंबई में सीबीआई की टीम को जानकारी मिली थी कि एक म्यूल खाते (ठगों की मदद के लिए खोले गए खाते) में 02 जुलाई को एक ही दिन में अलग-अलग लोगों की बड़ी रकम आई। यह पैसा तुरंत ही देशभर में फैले सौ से ज्यादा म्यूल खातों में भेजा गया और वहां से आगे हजारों खातों में ट्रांसफर किया गया, ताकि असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो।

जांच में पता चला कि यह खाता बैंक अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से बिना जरूरी केवाईसी और जांच के खोला गया था। इससे रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और बैंक के नियमों का उल्लंघन हुआ। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने मोबाइल फोन, आईपैड, बैंक दस्तावेज, लेन-देन की जानकारी और कई डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों के नाम सुधीर भास्कर पलांडे, यश ठाकुर और शौर्य सुनीलकुमार सिंह हैं। सुधीर म्यूल खाताधारक हैं, यश बिचौलिया और शौर्य ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे।

सीबीआई के मुताबिक, मुंबई में खाता खोलने से लेकर नागपुर में खाताधारक की ठहरने की व्यवस्था और पैसों को दूसरे खातों में भेजने में कई लोग शामिल थे। नागपुर के एजेंट और खाताधारक ने अपना कमीशन क्रिप्टो करेंसी में लिया, जिसे बाद में बाकी साथियों में बांट दिया गया।

ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से 10 मिनट पहले शर्तें लाना ठीक नहीं : किरेन रिजिजू

एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को एक बार फिर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। दोपहर 12 बजे सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्षी दलों ने संसद की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर नारेबाजी की और हंगामा काटा, जिसके बाद संसद की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने से पहले ही लोकसभा स्थगित होने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे। 16 घंटे का समय दिया गया था, ऐसे में अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले शर्तें लाना ठीक नहीं है। किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सवाल किया कि आखिर वह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा, सदन में सब तैयार थे, सभी दलों का मत था कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर 12-15 बजे चर्चा शुरू

होनी थी, उससे 10 मिनट पहले विपक्षी दलों ने एक नया मुद्दा उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले सरकार एक लाइन ऑफ कमिटमेंट दे कि इसके बाद एसआईपर चर्चा होगी, संसद ऐसे नहीं चलती। सदन में एक-दूसरे की बात सुनकर और फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक करके फैसला लिया जाता है, जब ये तय हुआ था कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे और 16 घंटे का समय दिया गया था, तो अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले शर्तें लाना ठीक नहीं है। कांग्रेस और विपक्षी दल अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आपने दो महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। हमने पहले दिन से ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। अब आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे है ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, कुछ देर पहले विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा से भागने का नाटक किया है, वह ठीक नहीं है। जब संसद दोबारा शुरू होगी तो जो शर्तें लेकर वे आए हैं वह नहीं चलेंगी। (ऑपरेशन सिंदूर) पर रक्षा मंत्री शुरुआत में प्रस्ताव रखेंगे और जब रक्षा मंत्री चर्चा शुरू करें तो उनकी बात सुनें और विपक्षी दल पाकिस्तान की भाषा न बोलें। हमारे सेना का मनोबल गिराने वाली बात न करें।

पहलगाम हमले पर पी. चिदंबरम के बयान से विवाद, प्रह्लाद जोशी ने दिया करारा जवाब

एजेंसी

नई दिल्ली । पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने पाकिस्तान को 'क्लीन चिट' दे दिया है। उन्होंने हाल ही में पूछा कि कैसे मान लिया जाए कि आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे, जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कड़ा पलटवार किया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पी. चिदंबरम के हालिया बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आईएएनएस से खास बातचीत में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी नीति रही है। जब चिदंबरम खुद गृह मंत्री थे, तब भी 'भगवा आतंकवाद' जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई थी। आज जब पूरा देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की भूमिका को लेकर प्रमाण देख रहा है, ऐसे में एक जिम्मेदार पूर्व मंत्री का इस तरह का बयान पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत करता है।प्रह्लाद जोशी ने आगे कहा कि यही लोग जब सत्ता में थे, तब भी पाकिस्तान के बचाव में खड़े नजर आते थे। अब सरकार ने पुख्ता

सबूतों के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भूमिका उजागर की है, तब भी ये बयान पाकिस्तान के स्टैंड को बल देने वाले हैं। इस दौरान, सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी की समीक्षा की जाएगी। इस पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने ऐतराज जताया और कहा कि तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि वे शराबबंदी को चालू रखना चाहते हैं या समाप्त करना चाहते हैं।

उनकी मंशा क्या है, यह अभी तक साफ नहीं है। रूडी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी से गरीबों को अप्रत्याशित लाभ हुआ है। बिहार की महिलाएं आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय के साथ मजबूती से खड़ी हैं। ताजा सर्वे भी यही बताता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता और विश्वसनीयता का एक बड़ा आधार यही शराबबंदी रही है। जो लोग इसे राजस्व हानि का तर्क देकर हटाना चाहते हैं, वे यह नहीं समझते कि बिहार बिना शराब के भी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

तीज महोत्सव नारी सशक्तिकरण और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक : रेखा गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तीज महोत्सव नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक बनकर सामने आया है। यह बातें मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित तीन दिवसीय तीज महोत्सव 2025 के समापन समारोह में कही। तीज महोत्सव 25 जुलाई से 27 जुलाई तक दिल्ली हाट पीतमपुरा आयोजित किया गया। समापन के मौके पर दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों की महिला सांसदों की भागीदारी ने तीज महोत्सव के आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने तीज को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि महिला चेतना और सांस्कृतिक आंदोलन का प्रतीक बताया। उन्होंने कार्यक्रम में आई महिलाओं से मुलाकात की और आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों की उपस्थिति

किसी भी कार्यक्रम को सुंदर बना देती है। इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में मेरी बहनों की उपस्थिति से यह साबित होता है कि तीज को लेकर महिलाओं में कितना उत्साह है। हमने तीज के इस सुन्दर अवसर पर अपनी बहनों के लिए झूले, मेंहदी फ्री लगवाने का इंतजाम किया है। हम हर वर्ष इसी भव्यता के साथ तीज का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त दिल्ली के सांसद भी उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजन को अपना समर्थन दिया। महोत्सव में 100 से अधिक स्टॉल्स, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन, बच्चों के लिए किड्स ज़ोन, रंगोली, मेहंदी, सेल्फी प्वाइंट्स, झूले, स्लोगन और क्विज प्रतियोगिताएं शामिल की गईं। आयोजन का डिजिटल प्रचार 'बुक माय शो' और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से व्यापक रूप से किया गया। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन पूरी तरह निःशुल्क था और इसका उद्देश्य महिला उद्यमिता व रचनात्मकता को मंच देना था। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव दिल्ली को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है।महोत्सव का शुभारंभ मशहूर गायक जसबीर सिंह के मनमोहक संगीत से हुआ, जबकि समापन समारोह में जानी-मानी गायिका शिवानी कश्यप ने अपनी ऊर्जावान प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

डिंपल यादव के समर्थन में संसद के बाहर राजग सांसदों का प्रदर्शन

एजेंसी

नई दिल्ली। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन (एआईआईए) के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी द्वारा एक टेलीविजन बहस के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा)की सांसद डिंपल यादव पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। राजग के घटक दलों की सभी महिला सांसदों ने इस टिप्पणी की निंदा की है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही राजग सांसदों ने डिंपल यादव के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मौलाना साजिद रशीदी ने सपा प्रमुख की पत्नी और सांसद डिंपल यादव को लेकर एक टिप्पणी की थी। मौलाना रशीदी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें

मौलाना यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मस्जिद में हुई बैठक में सपा की तरफ से दो महिलाएं बैठी हैं। एक इकरा हसन हैं जो सर ढक कर बैठी हैं। इसी के बाद मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर कमेंट किया।

लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025 लाने की तैयारी में दिल्ली सरकार : सिरसा

एजेंसी

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार अपनी लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी 2025 लाने की तैयारी में है। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ड्राफ्ट में पहले ही ऐसे कदम शामिल हैं, जो न केवल दिल्ली का ट्रैफिक जाम कम करेंगे बल्कि प्रदूषण घटाएंगे और व्यापार की कार्यक्षमता बढ़ाएंगे। सरकार डेडिकेटेड लॉजिस्टिक्स हब, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर और टेक्नोलॉजी आधारित समाधान लागू करने की दिशा में काम कर रही है–ये पहल ट्रैफिक कम करने, प्रदूषण घटाने और व्यापार करने में आसानी लाने का वादा करती हैं। यह जानकारी एक जारी करके दी है। मंत्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली में हर दिन 10 लाख टन माल का लगभग 1.93 लाख वाहनों के जरिए आवागमन होता है, जिनमें से 21 फीसद वाहन ट्रैफिक से होकर गुजरते हैं । सबसे ज्यादा वाहन बिल्डिंग मटेरियल (4,132 वाहन/दिन), टेक्सटाइल (3,995), फल-सब्जियां (2,569) और खाद्य उत्पाद (2,468) लाते हैं, जबकि फार्मास्युटिकल (559) और ऑटोमोबाइल (588) भी ट्रैफिक से गुजरते हैं। सही वेयरहाउसिंग जोन न होने से ये वाहन शहर के अंदरुनी

हिस्सों में आते हैं, जिससे प्रमुख मार्गों पर जाम और प्रदूषण बढ़ता है। उद्योग मंत्री सिरसा ने बताया कि ड्राफ्ट पॉलिसी में वेयरहाउस को शहर की सीमा पर शिफ्ट करना, आधुनिक अर्बन कंसॉलिडेशन और लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर (यूसीएलडीसीएस) पर माल कंसॉलिडेट करना, और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल शामिल है। ये कदम आजादपुर, गाजीपुर, नारायणा और करोल बाग जैसे हॉटस्पॉट्स पर जाम और प्रदूषण कम करने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि नई पॉलिसी 1 प्रमुख एक्शन पॉइंट्स पर आधारित है, जो दिल्ली के लॉजिस्टिक्स ढांचे को पूरी तरह बदल देंगे।

मुख्य पहलों में 24×7 संचालन के लिए मॉडल शॉप्स एक्ट में बदलाव, डिजिटल डिलीवरी मैनेजमेंट जिससे ट्रक मूवमेंट नियंत्रित हो और पीक ट्रैफिक घटे,पीपीपी मॉडल के तहत कमर्शियल पार्किंग एरिया और लोडिंग बे का निर्माण, ट्रेड और एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस का मर्जर शामिल हैं, ये सभी कदम ट्रक पार्किंग की कमी से लेकर पुराने फ्रेट हैंडलिंग सिस्टम तक की समस्याओं को खत्म करेंगे। इससे दिल्ली की सप्लाई चेन अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी।

प्रधानमंत्री मोदी से असम के सीएम डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने की मुलाकात

एजेंसी

गुवाहाटी/नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को मुलाकात की और राज्य के विकास योजनाओं पर

चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उन्हें (प्रधानमंत्री) सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में असम की उल्लेखनीय प्रगति और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लगभग पूर्ण होने के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि असम की जनता की ओर से, मैंने 8 सितंबर को असम में उनका स्वागत करने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की। यह एक ऐसा क्षण होगा जो हमारे राज्य की विकास यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. सरमा इन दिनों दिल्ली प्रवास पर हैं। प्रवास के दौरान उनका कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम निर्धारित है।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने की राज्यसभा के उपसभापति से मुलाकात

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर गुप्ता ने उपसभापति को दिल्ली विधानसभा में चल रहे विभिन्न परिवर्तनकारी कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने विधानसभा को एक आदर्श लोकतांत्रिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए अपनाई जा रही कार्ययोजनाओं के बारे में बताया। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेजी से प्रगति कर रही है और आगामी मानसून सत्र से पहले इसके पूर्ण होने की संभावना है। यह परियोजना सदन की कार्यवाही और विधायी दस्तावेजों तक सरल डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करेगी, जिससे विधानसभा का सम्पूर्ण कार्य डिजिटल स्वरूप में संचालित हो सकेगा। उन्होंने आगे बताया कि पर्यावरणीय सततता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत विधान सभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर

ऊर्जा पर आधारित बन जाएगी, और यह देश की पहली हरित विधानसभा के रूप में एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा पुस्तकालय का डिजिटलीकरण कार्य भी प्रगति पर है, जिसका उद्देश्य विधायकों एवं कर्मचारियों को अनुसंधान और ऐतिहासिक अभिलेखों तक सुलभ और आधुनिक पहुंच प्रदान करना है। दिल्ली विधान सभा परिसर को राष्ट्रीय महत्व की विरासत स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी ठोस योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे इस ऐतिहासिक भवन की वास्तुकला और लोकतांत्रिक विरासत को संरक्षित किया जा सके। गुप्ता ने कहा कि ये सभी पहलें दिल्ली विधानसभा को एक डिजिटल रूप से सशक्त, पर्यावरण अनुकूल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध संस्थान के रूप में स्थापित करने की व्यापक दृष्टि का हिस्सा हैं। इन प्रयासों के माध्यम से देश की अन्य विधान सभाओं के साथ सहयोग और लोकतांत्रिक प्रगति को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की इन दूरदर्शी पहलों की सराहना की ।

राष्ट्र निर्माण की चेतना को घर-घर तक पहुंचाता है मन की बात कार्यक्रम: रेखा गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समयपुर स्थित श्री नारायण सिंह नेताजी फार्म में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 124वें संस्करण को भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ सुना। मुख्यमंत्री ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनसंवाद की वह धारा है, जो राष्ट्र निर्माण की चेतना को घर-घर तक पहुंचाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के इस प्रेरक एपिसोड में प्रधानमंत्री ने जनभागीदारी, भारतीय संस्कृति, सेवा और आत्मनिर्भर भारत की भावना को नई दिशा व ऊर्जा दी। उन्होंने देश की मिट्टी से उपजी कहानियों, नवाचारों और सेवा भावना से

ओतप्रोत विचारों ने प्रत्येक श्रोता के हृदय को स्पर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संवाद केवल विचारों का साझा मंच नहीं, बल्कि संकल्प से सिद्धि की दिशा में पूरे राष्ट्र को प्रेरित करने वाला एक जन-आंदोलन है। इस अवसर पर सांसद योगेन्द्र चंदौलिया, विधायक दीपक चौधरी एवं उत्तर-पश्चिम दिल्ली भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद सेहरावत उपस्थित रहे। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' के 124वें संस्करण को सुना। विजेंद्र गुप्ता ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस संवाद में प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक वापसी, भारत के ऐतिहासिक किलों को अमूल्य धरोहर, स्वदेशी आंदोलन और वस्त्र उद्योग के उत्थान, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, मछली पालन जैसे सराहनीय पहलों तथा स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन बनाने पर प्रेरक विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम हमें देश की संस्कृति, आत्मनिर्भरता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम है।

संपादक की कलम से

अराजकता की ओर बढता भारत, ब्रेक कौन लगाएगा?

यदि आप भारत में हैं तो आप कानून को ठेंगे पर रख सकते हैं. किसी को भी सडक चलते पीट सकते हैं, पिट सकते हैं. कहीं भी पेशाब कर सकते हैं, कहीं भी थूक सकते हैं. कहीं भी अपना वाहन खडा कर सकते हैं. क्योंकि भारत में राम राज आ चुका है. छोटे मोटे कानून तो आपके खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं हो सकते. यहाँ तक कि आप किसी भी मंत्री को, नेता को जान से मारने की धमकी आसानी से दे सकते हैं.ताजा खबर है कि केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ को जान से मारने की धमकी मिली है। शुक्रवार को फोन करके उन्हें
धमकी दी गई है ।धमकी देने वाले का पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस इसका पता लगा रही है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दी है। धमकी देने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है।संजय सेठ रांची से भारतीय जानता पार्टी के संसद हैं. साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की. इसका इनाम उन्हें मंत्रीपद के रूप में मिला. सेठ तो सेठ ठहरे मप्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रह चुके डॉ गोविन्द सिंह को भी किसी ने फोन कर जान से मारने की धमकी दे डाली. मप्र पुलिस भी इस धमकी को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है. पूरे देश में यही आलम है. आप दो पक्षों के बीच सरेराह होने वाले झगडे में बीचबचाव नहीं कर सकते. ग्वालियर में एक ऐसे ही मामले में गुंडों ने एक हैडकानेस्टबल का सिर फोड दिया. एक सब इंसपेक्टर ने भोपाल में दो लडकियों के साथ सरेआम अभद्रता की, लेकिन कुछ नहीं हुआ.हमारे यहां कानून का कोई इकबाल नहीं. हमारी सरकार, हमारी शिक्षा पद्यतिपिछले आठ दशक में आम आदमी को सडक पर बांयी तरफ चलना नहीं सिखा पायी, ऊपर से तुर्रा ये कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं. देखने में बात बहुत हलकी लगती है लेकिन है बहुत बडी. बडी इसलिए कि ये छोटे छोटे कानूनों की अनदेखी हमें लगातार असभ्य बना रही है।

इसी से घबडाकर सालाना दो लाख से अधिक भारतीय विदेशों की नागरिकत ले रहे हैं. किंतु सरकार को, भाजपा को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई परवाह नहीं. उन्हे तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, भले ही देश अराजक हालात में पहुंच जाए.

मेरी पक्की धारणा है कि हम भारतीय शायद ही सभ्य हो पाएंगे. असभ्यता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. कानून का मान मर्दन हमारे लिए मात्र मनोरंजन है. मनोरंजन के सिवा कुछ नहीं.

महाराष्ट्र में आप हिंदी न बोलने पर पीटे जा सकते हैं. मराठियों के बारे में बोलने पर बडबोले निशिकांत दुबे को भी महाराष्ट्र आने पर पीटने की धमकी दी जा सकती है. संघ प्रमुख जब खुद डर के भीतर अपने आप को असुरक्षित समझते हैं. वे सार्वजनिक रूप से डर की बात कह चुके हैं. बिहार में एक के बाद हत्या की वारदात हो चुकी हैं लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं है. बदलाव नही है.

प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान चलवाया, 12करोड से ज्यादा घरों में शौचालय बनवा दिए लेकिन नतीजा सिफर है. वजह है हमारी मानसिकता, हमारी दंडप्रणाली. हम कचरा फेंकने, सडक किनारे पेशाब या शौच करने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या धूम्रपान करने को अपराध मानते ही नहीं, हालांकि हमारे कानून के अनुसार ये सब दंडनीय अपराध हैं.

विदेश से स्वदेश की धरती पर पांव रखते ही हमें गंदगी के दर्शन हो जाते है. हवाई अड्डे के बाहर निकलते ही गंदगी और दुर्गंध हमारा स्वागत करती है. सडकों के दोनों और खडी खरपतवार और गंदगी के ढेर हमारे सौंदर्यबोध का मुजाहिरा करते हैं. इस सबके लिए अकेले मोदीजी जिम्मेदार नहीं हैं. नेहरू भी जिम्मेदार हैं, इंदिरा गांधी भी जिम्मेदार हैं.हम सब जिम्मेदार हैं.पुलिस, अदालत, स्थानीय निकाय, स्कूल, सब इस अराजकता के लिए दोषी हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हमारे जन प्रतिनिधियों की रक्षा करे धमकीबाजों से.

विश्व हेपेटाइटिस दिवस: एक दिन नहीं, हर दिन का अभियान

एक अदृश्य हत्यारा, जो बिना आवाज किए लाखों जिंदगियों को निगल जाता है। वह चुपके से जिगर को खोखला करता है, सपनों को कुचल देता है, और परिवारों को बिखेर देता है। यह है हेपेटाइटिस–एक ऐसी बीमारी, जो न दर्द की चेतावनी देती है, न ही कोई आहट। जब तक इसका पता चलता है, तब तक बहुत कुछ छिन चुका होता है। हर साल 28 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें इस खामोश शत्रु के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता है। यह दिन केवल जागरूकता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक संकल्प है–एक स्वस्थ, हेपेटाइटिस-मुक्त विश्व के निर्माण का। यह उन लाखों लोगों की पुकार है, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और उन अनगिनत परिवारों की उम्मीद, जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। हेपेटाइटिस यकृत (लिवर) की सूजन है, जो मुख्य रूप से पांच प्रकार के वायरस, अ, इ, उ, ऊऔर ए, के कारण होती है। इनमें से हेपेटाइटिस इ और उ सबसे खतरनाक हैं, जो विश्व स्तर पर लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, विश्व में लगभग 35.4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस इ और उ से पीड़ित हैं, और हर साल करीब 13 लाख लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवाते हैं। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां अनुमानित 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस इ और 1.2 करोड़ लोग हेपेटाइटिस उ से प्रभावित हैं। सबसे दुखद पहलू यह है कि इनमें से 80% से अधिक लोगों को अपनी बीमारी का पता तब तक नहीं चलता, जब तक यकृत को गंभीर क्षति न हो जाए। यह एक ऐसी बीमारी है जो चुपके से हमला करती है, और जब तक लक्षण जैसे त्वचा का पीलापन (जॉन्डिस), थकान, भूख न लगना, या पेट दर्द उभरते हैं,

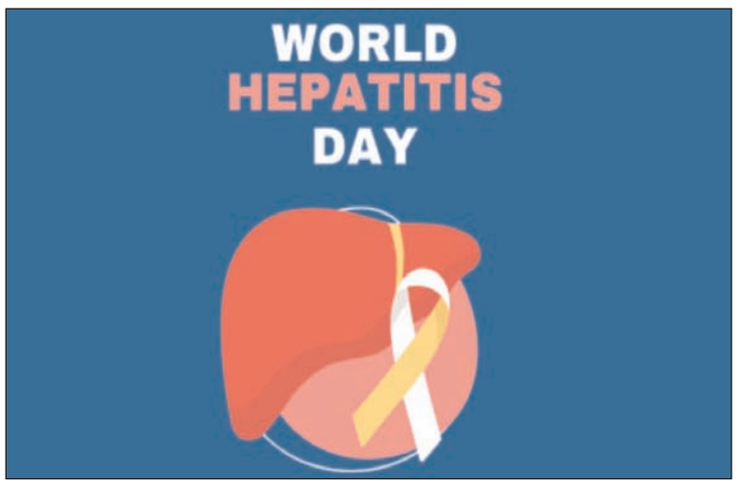

तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेपेटाइटिस का प्रसार कई रूपों में होता है। हेपेटाइटिस अ और ए दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलते हैं, जो खराब स्वच्छता और अपर्याप्त जल प्रबंधन का परिणाम हैं। वहीं, हेपेटाइटिस इ और उ का प्रसार संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध, साझा सूइयों, असुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं और जन्म के दौरान माता से शिशु में होता है। हेपेटाइटिस ऊ केवल हेपेटाइटिस इ से संक्रमित लोगों को प्रभावित करता है, जिससे बीमारी और जटिल हो जाती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती इसकी मौन प्रकृति है। शुरूआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं–थकान, हल्का बुखार, भूख में कमी–कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब गंभीर लक्षण सामने आते हैं, तब यकृत को अपूरणीय क्षति हो चुकी होती है, और इलाज की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का उद्देश्य इस बीमारी के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, जांच और उपचार को बढ़ावा देना, और इसे समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए तीन प्रमुख रणनीतियां अपनाई गई हैं: टीकाकरण, सुरक्षित चिकित्सा प्रथाएं, और प्रभावी उपचार तक पहुंच। हेपेटाइटिस इ का टीका, जो 1982 में विकसित हुआ, इस दिशा में एक वरदान है। यह टीका 95% से अधिक प्रभावी है और नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटों के भीतर पहला डोज देना अनिवार्य है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत यह टीका मुफ्त उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी इसे प्रभावी बनाने में बाधा डालती है। हेपेटाइटिस उ के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष-अभिनय एंटीवायरल दवाएं 95% से अधिक मामलों में पूर्ण इलाज प्रदान करती हैं। हालांकि, इन दवाओं की उच्च लागत और जांच तक सीमित पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती है। भारत में हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई कई बाधाओं से जूझ रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की असमानता, असुरक्षित रक्त आधान, और सामाजिक कलंक इस बीमारी के प्रसार को बढ़ाते हैं। कई लोग डर, शर्मिंदगी, या जानकारी के अभाव में जांच से बचते हैं। विशेष रूप से नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेने वाले लोग और असुरक्षित यौन संबंधों में लिप्त लोग इस बीमारी के उच्च जोखिम में हैं, लेकिन सामाजिक बहिष्कार के कारण वे स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की कमी और दूषित पानी हेपेटाइटिस अ और ए के प्रसार को बढ़ावा देता है। इन सभी चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी नीतियों या स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों से संभव नहीं है।

इसके लिए समाज के हर वर्ग–चाहे वह शिक्षक हों, छात्र हों, या सामुदायिक नेता–को जागरूकता फैलाने और सक्रिय भागीदारी निभाने की जरूरत है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 की थीम, "हेपेटाइटिस को समझें, इसे मिटाने के लिए अभी कदम उठाएं", हमें इस खामोश हत्यारे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आह्वान देती है। यह एक जागृति की पुकार है, जो हर व्यक्ति को इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और डिजिटल मंचों के जरिए जानकारी का प्रसार इस दिशा में निर्णायक कदम हो सकता है। स्वास्थ्यकर्मियों को हर मरीज में लक्षणों की गहन जांच और समय पर निदान को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि एक क्षण की देरी जानलेवा हो सकती है। भारत सरकार का राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी), जो 2018 में शुरू हुआ, मुफ्त जांच और उपचार के जरिए लाखों जिंदगियों को बचा रहा है। लेकिन असली जीत तब होगी, जब हर नागरिक इस मिशन में शामिल हो और हेपेटाइटिस को जड़ से उखाड़ने का संकल्प ले। यह लड़ाई हमारी है, और समय अभी है।

हेपेटाइटिस केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है; यह सामाजिक और आर्थिक बोझ भी लाती है।

इस बीमारी से प्रभावित परिवार अक्सर इलाज के खर्च, सामाजिक बहिष्कार, और मानसिक तनाव से जूझते हैं। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि हम इस बीमारी को गंभीरता से लें और इसे सामाजिक चर्चा का हिस्सा बनाएं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें यह मौका देता है कि हम न केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हों, बल्कि अपने समुदाय को भी शिक्षित करें। आज, जब विज्ञान ने हमें टीकाकरण, प्रभावी दवाएं, और जागरूकता के लिए डिजिटल मंच जैसे साधन दिए हैं, तब यह और भी दुखद है कि हम इस बीमारी के सामने हार रहे हैं। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए मर रहे हैं, क्योंकि हमने समय पर कदम नहीं उठाया। यह समय है कि हम इस खामोश हत्यारे के खिलाफ एकजुट हों। अपने और अपनों के लिए जांच करवाएं, टीकाकरण को अपनाएं, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। विश्व हेपेटाइटिस दिवस एक तारीख से कहीं अधिक है–यह एक संकल्प है, एक जिम्मेदारी है, और एक मौका है कि हम उन लाखों जिंदगियों को बचा सकें जो अभी भी इस बीमारी की चपेट में हैं।

इस 28 जुलाई को हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि जब बात जीवन की हो, तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। जानकारी, सतर्कता, और समय पर कार्रवाई–यही वह हथियार हैं जो हमें इस लड़ाई में विजयी बनाएंगे।

प्रो. आरके जैन अरिजीत, बड़वानी (मप्र)

ट्रंप की सनक या तानाशाही

अपने अनिश्चित स्वभाव के अनुरूप, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था के साथ बहुत अधिक खिलवाड़ किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान प्रवासी विरोधी बनता जा रहा है। ट्रंप की टेक कंपनियों को उनकी ताजा चेतावनी इसी का प्रमाण है। जिसे राष्ट्रपति चुने जाने के लिए भारत में हवन पूजन किया गया हो। जिसे देश के प्रधानमंत्री का बेहतर मित्र कहा जा रहा हो वह राष्ट्रपति भारत के खिलाफ लगातार आग उगल रहा है।हालांकि ट्रंप की ऐसी हर कोशिश उनके ही देश को नुकसान पहुंचाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जबसे अमेरिकी राष्ट्रपति पद को संभाला है, भारत के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला और कहा कि अब वो दिन लद गए जब अमेरिकी कंपनियां भारतीयों को नौकरी दें। इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को एक सख्त मैसेज दिया है, जिसमें भारत से हायरिंग करने को मना किया है। ऐसे कई फैसले जो उन्होंने भारत को हानि पहुचाने वाले लिए है। दूसरे कार्यकाल की शुरूआत ही धमकियों से करने वाले ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां केवल अमेरिकियों को ही नौकरी दें। उनका कहना है कि हमारी कई बड़ी टेक कंपनियों ने अमेरिकी आजादी का फायदा उठाते हुए चीन में फैक्ट्रियां बनाईं, भारत में कर्मचारियों को

नौकरी दी और आयरलैंड में मुनाफा बचाया...। कुछ अरसा पहले ही ट्रंप ने एपल को चेतावनी दी थी कि अगर उसने भारत में प्रॉडक्शन किया, तो आईफोन पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में बिकने वाला हर सामान अमेरिका में ही बने और उसे बनाएं भी अमेरिकी ही, लेकिन क्या यह संभव है? ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब मुक्त व्यापार की बात हो रही है, तब कोई अर्थव्यवस्था खुद में सिमट कर नहीं रह सकती। और सबसे अहम बात, अमेरिकी कंपनियां इसलिए भारत या चीन में प्लांट लगाना चाहती हैं, क्योंकि यहां मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है। इसी तरह, सिलिकॉन वैली या दूसरी अमेरिकन इंडस्ट्रीज में भारतीयों ने अपनी बुद्धिमत्ता से जगह बनाई है। दर्जनों विश्व विख्यात कम्पनी के मुख्यकर्ताधर्ता भारतीय मूल के है। सिलिकॉन वैली के करीब एक तिहाई टेक एम्प्लॉई भारतीय मूल के हैं। फॉर्च्युन 500 की लगभग डेढ़ दर्जन कंपनियों में टॉप पोजिशन पर भारतीय बैठे हैं। ये भारतीय अमेरिकी इकॉनमी के इंजन हैं। 2024 में 72 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारतीय मूल के लोगों के थे और इनकी टोटल वैल्यू 195 अरब डॉलर आंकी गई थी। इन कंपनियों में अमेरिकी भी काम करते हैं। इसी तरह, अमेरिका की आबादी में 1.5 वाले भारतीय 5-6: इनकम टैक्स अदा करते हैं।अमेरिकी की टेक इंडस्ट्री या सिलिकॉन वैली आज अगर वैश्विक स्तर पर राज कर रही है, तो इसमें प्रवासियों का बड़ा योगदान है।

दुनियाभर की मेधा, खासकर भारत की, ने मिलकर इस इंडस्ट्री को सींचा है। इलॉन मस्क की टेस्ला को जब ऑटोपायलट सॉफ्टवेयर में सफलता मिली, तो उन्होंने भारतीय मूल के एक रोबोटिक्स इंजीनियर अशोक एल्लुस्वामी का ही नाम पहले लिया था।

ट्रंप उस वैश्वीकरण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ है। उनके पास इंडस्ट्री की मांग को पूरा करने लायक वर्कफोर्स नहीं है। भारत के बिना उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पूरा नहीं हो सकता।वैसे भी जब से ट्रप ने पद सम्हाला है तब से संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार परिदृश्य एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में 20 से ज्यादा देशों में अपने टैरिफ अभियान का विस्तार कर रहे हैं। 50 प्रतिशत तक के प्रतिशोधात्मक शुल्कों के साथ, ऑटोमोबाइल और एल्युमीनियम से लेकर तांबा और ई-कॉमर्स तक, सभी क्षेत्र इस टकराव में फँस गए हैं। इसके लिए कनाडा, ब्राजील और भारत जैसे देश छूट हासिल करने के लिए 1 अगस्त की समय सीमा के खिलाफ दौड़ रहे हैं। जबकि व्यवसाय और उपभोक्ता इसके बाद के झटकों के लिए तैयार हैं। यानि इतना तो तय है कि या तो ट्रम्प किसी सनक का शिकार हो गए है फिर उनको तानाशाही करने में मजा आ रहा है। लेकिन हिन्दुस्तान में यह कहावत आम है कि अकेल चना भाड़ नही फोड़ सकता। इसका आभास जल्द ही ट्रम्प को हो जाएगा।

मोटापा है कई बीमारियों की जड़, कैंसर का भी बढ़ाता है खतरा :

दुनियाभर समेत भारत में भी मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है. इसके बढ़ते खतरे को लेकर एम्स के डॉक्टरों ने भी अलर्ट किया है.एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ दीपक गुंजन का कहना है कि मोटापा सिर्फ दिखने भर की समस्या नहीं है बल्कि इसके पीछे कई गंभीर बीमारियों का खतरा छिपा होता है. उन्होंने बताया कि जब शरीर में फैट बढ़ता है तो फैट सेल्स एक अंग की तरह काम करने लगते हैं और कई तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं।ये हार्मोन कैंसर को बढ़ावा दे सकते हैं. डॉ गुंजन के मुताबिक, मोटापा की वजह से कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पेट का कैंसर (स्टमक कैंसर) होने का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि कैंसर सिर्फ एक हिस्सा है. मोटापा हार्ट डिजीज,नींद में गड़बड़ी (स्लीप एप्निया), मांसपेशियों की कमजोरी और कई दूसरी बीमारियों की भी वजह बन सकता है. उन्होंने बताया कि अगर मोटापे पर समय रहते कंट्रोल पा लिया जाए तो इन बीमारियों से भी बचा जा सकता है. मोटापा पता लगाने के लिए बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) एक आसान तरीका है, जिससे समझा जा सकता है कि आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से सही है या नहीं.

ज्यादा नमक और चीनी सेहत के लिए खतरा

डॉ गुंजन ने खाने-पीने की आदतों को लेकर भी अहम बातें बताईं. उन्होंने कहा कि आज के समय में जरूरत से ज्यादा नमक और चीनी लेना सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है. अगर चीनी और नमक को सीमित मात्रा में लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता. खासतौर पर नमक पूरी तरह छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि स्वाद बिगड़ जाता है लेकिन इसकी मात्रा रोजाना 5 ग्राम से कम होनी चाहिए.

चीनी के बारे में उन्होंने बताया कि यह कोई पुरानी चीज नहीं है बल्कि एक नया आविष्कार है. मिठास के लिए और भी कई प्राकृतिक विकल्प मौजूद हैं. काबोर्हाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों से भी शरीर को शुगर मिल जाती है इसलिए अतिरिक्त चीनी की जरूरत नहीं होती.

डॉ गुंजन का कहना है कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित डाइट,अच्छी नींद और नियमित एक्सरसाइज बेहद जरूरी हैं. उन्होंने एक आसान उदाहरण देकर समझाया, जैसे बैंक में जितना पैसा डालते हैं, अगर उतना ही निकालते हैं तो बैलेंस बना रहता है. वैसे ही शरीर में जितनी कैलोरी आप खाते हैं उतनी ही खर्च भी करनी चाहिएय अगर खर्च नहीं करेंगे तो वो कैलोरी फैट बनकर जमा हो जाएगी.

फैटी लिवर की भी बढ़ रही समस्या

फैटी लिवर डिजीज कैंसर का भी कारण भी बन रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण होता है खराब लाइफ स्टाइल. अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से फैटी लिवर होता है. इसके लिए जरूरी है कि तेल कम खाएं, एक्सरसाइज रेगुलर करें तो फैटी लिवर नहीं होगा. साथ ही शराब का सेवन भी न करें क्योंकि ये भी लिवर पर असर करती है.

स्वामी शिवानंद ने बदल दी डॉ. कलाम की जीवन दिशा

कुमार कृष्णन

तारीख थी 27 जुलाई, साल था 2015... और शाम ढल चुकी थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलॉन्ग का एक सभागार छात्रों से भरा पड़ा था। मंच से एक जाने-माने शख्स सबको संबोधित कर रहे थे लेकिन तभी अचानक खामोश हो गए। अचानक लड़खड़ा कर गिरे तो उठ नहीं पाए। बाद में खबर आई तो निधन की। ये कोई और नहीं बल्कि मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने जीवन भर देश को शक्तिसंपन्न और आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा।

स्वामी शिवानंद की मुलाकात ने उनकी जीवन की दिशा बदल डाली। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मानसिक शांति की खोज में स्वामी शिवानंद के आश्रम पहुंचे। स्वामीजी का भव्य व्यक्तित्व देखकर कलाम बहुत प्रभावित हुए। जब उन्होंने स्वामीजी को अपना परिचय दिया तो वे बड़े स्नेह से उनसे मिले। कलाम ने उस भेंट के विषय में एक जगह लिखा है- मेरे मुस्लिम नाम की उनमें जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने उन्हें वायुसेना में अपने नहीं चुने जाने की असफलता के विषय में बताया तो वे बोले- इच्छा, जो तुम्हारे हृदय और अंतरात्मा से उत्पन्न होती है, जो शुद्ध मन से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा हर रात को आकाश में चली जाती है और हर सुबह ब्रह्मांडीय चेतना लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। अपनी इस दिव्य ऊर्जा पर विश्वास रखो और अपनी नियति को स्वीकार कर इस असफलता को भूल जाओ।

नियति को तुम्हारा पायलट बनना मंजूर नहीं था, अतः असमंजस और दुख से निकलकर अपने लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। स्वामी शिवानंद के शब्दों ने जादू-सा असर दिखाया और कलाम ने दिल्ली आकर डीटीडीएंडपी जाकर अपने साक्षात्कार का नतीजा पता किया। नतीजा उनके पक्ष में था और वे वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त हुए। आगे चलकर वे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। कभी इच्छा, संकल्प और प्रयत्न के बावजूद भाग्य साथ नहीं देता है, किंतु इससे निराश होने के स्थान पर स्थिर चित्त से विचार कर कार्य-दिशा कुछ परिवर्तित करते हुए दोगुने उत्साह से प्रयत्नशील होना चाहिए।

अंततः सफलता अवश्य मिलती है।डॉ. कलाम ने अपनी किताब अग्नि की उड़ान और माय जर्नीः ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन में इस वाकये का जिक्र किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद वे दो बार मुंगेर आए और बिहार योग विद्यालय में प्रज्ज्वलित स्वामी शिवानंद जी की अखंड ज्योति का साक्षात्कार किया। वे यहां राष्ट्रपति नहीं एक शिष्य की तरह पधारे। वे आजन्म गुरूओं के शिष्य बने रहे। कलाम साहब आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं लेकिन, उनकी आवाज आज भी स्कूलों में, किताबों में, मिसाइल प्रक्षेपणों में और हर उस युवा के सपनों में गूंजती है, जो कुछ बड़ा करना चाहता है।

डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉ. अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम का जीवन कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस मछुआरे के बेटे की गाथा है, जिसने रामेश्वरम की गलियों से चलकर राष्ट्रपति भवन की दहलीज तक का सफर तय किया और मिसाइल तकनीक से लेकर बच्चों के मन तक में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ।

कारगिल युद्ध और समीक्षा समिति की विरासतः अग्निवीर नीति के आलोक में

जयसिंह रावत

1999 का कारगिल युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण बनकर उभरा। इस संघर्ष ने जहां भारतीय जवानों की वीरता को अमर कर दिया, वहीं देश की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी बेनकाब किया। इस युद्ध के बाद स्थापित कारगिल समीक्षा समिति ने भारत की रक्षा नीति, खुफिया व्यवस्था, सैन्य समन्वय और भर्ती नीति में व्यापक सुधारों की सिफारिश की थी। वर्तमान में जब अग्निवीर योजना को लागू किया गया है तो यह समझना आवश्यक है कि क्या यह योजना कारगिल युद्ध की सीखों से उपजी है या उनसे विचलन का संकेत देती है।

कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि और सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा

कारगिल युद्ध पाकिस्तान द्वारा किए गए एक पूर्व नियोजित सैन्य अभियान का परिणाम था, जिसमें नियंत्रण रेखा पार कर भारत की रणनीतिक ऊँचाइयों पर कब्जा करने की कोशिश की गई।

प्रारंभिक खुफिया विफलताओं और सीमा निगरानी की चूकों ने इस युद्ध को संभव बनाया। युद्ध की समाप्ति के बाद देश के सामरिक ढांचे की समीक्षा के लिए डम्फ का गठन हुआ, जिसने कई ऐतिहासिक सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों में सैन्य बलों के युवाकरण, शॉर्ट सर्विस कमीशन के विस्तार, पैरा-मिलिट्री बलों से समन्वय और सीमा निगरानी के उन्नयन जैसे सुझाव शामिल थे। यही वह बिंदु हैं, जहां से वर्तमान अग्निपथ योजना का वैचारिक और प्रशासनिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

अग्निवीर योजनाः उद्देश्य, संरचना और चुनौतियाँ

अग्निवीर योजना, जिसे सरकार ने 2022 में लागू किया, भारतीय सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के पारंपरिक ढांचे को पूरी तरह बदलने का प्रयास है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को मात्र चार वर्षों के लिए भर्ती किया जाता है जिसमें से केवल 25% को भविष्य में स्थायी सेवा में रखा जाएगा जबकि 75% को सेवा के बाद समाज में पुनर्स्थापित होना होगा।

इस योजना के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे सेना की औसत आयु कम होगी, सेना में ऊर्जा और चुस्ती बनी रहेगी, और रक्षा बजट पर पेंशन का भार घटेगा

लेकिन, इस तर्क को की दृष्टि से परखना आवश्यक है। ने सेना में युवाकरण का समर्थन तो किया था लेकिन उसने जवानों की बहुत छोटी सेवा अवधि या बड़े पैमाने पर अस्थायी नियुक्तियों का सुझाव नहीं दिया था।

समिति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सेना में भर्ती को व्यावसायिक और स्थायी स्वरूप मिलना चाहिए ताकि उनमें कौशल, समर्पण और मनोबल बना रहे। इसके विपरीत, अग्निवीर योजना में भर्ती प्रक्रिया को एक संक्षिप्त अनुबंधीय रोजगार में बदला गया है जिससे न केवल सैनिकों का दीर्घकालीन प्रशिक्षण बाधित होगा।

बल्कि एक अनुभवी, प्रतिबद्ध और स्थायी बल का निर्माण भी कठिन हो जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा और मनोबल पर प्रभाव

सेना कोई सामान्य नौकरी नहीं बल्कि एक जीवन भर की प्रतिबद्धता है। चार साल की सेवा के बाद अगर 75% सैनिकों को छोड़ दिया जाता है, तो इससे न केवल उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होगी, बल्कि इसका प्रभाव उनके मनोबल, अनुशासन और युद्ध कौशल पर भी पड़ेगा। डम्फ ने अपने अध्ययन में इस बात पर जोर दिया था कि सैनिकों की विश्वसनीयता और स्थायित्व युद्धकालीन स्थितियों में निर्णायक सिद्ध होते हैं। सीमाओं की रक्षा के लिए ऐसा बल चाहिए जो अनुभव और आत्मबल से संपन्न हो।

अग्निवीर जैसी अल्पकालिक योजना से सैनिकों के भीतर दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि और युद्ध-कौशल की परिपक्वता विकसित नहीं हो पाएगी। इसके अतिरिक्त, भविष्य में नागरिक जीवन में उनकी पुनर्वापसी को लेकर भी गम्भीर प्रश्नचिह्न बने हुए हैं।

हालांकि सरकार ने अग्निवीरों के लिए उअढऋ पुलिस, फायर सर्विस और निजी क्षेत्र में अवसरों की बात कही है लेकिन इस संबंध में ठोस कानूनी या संस्थागत ढांचा अभी तक नहीं बनाया गया है। इसके अभाव में यह योजना केवल बेरोजगारी टालने या पेंशन बोझ घटाने का एक तात्कालिक उपाय प्रतीत होती है।

KRC की मूल भावना बनाम अग्निवीर योजना

डम्फ ने सेना को युवा और चुस्त बनाए रखने के लिए ररउ जैसे मॉडल का समर्थन किया लेकिन यह मॉडल अधिकारी वर्ग के लिए था जिसमें सेवा काल 5 से 14 वर्ष तक होता था। निचले रैंक के सैनिकों के लिए उसने सेवा की अवधि, पेंशन और परिपक्वता को बनाए रखने का समर्थन किया। समिति ने बार-बार बल दिया था कि सैनिकों को सेवा के पश्चात पैरा-मिलिट्री बलों में समायोजित करने की नीति अपनाई जाए जिससे सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों दोनों को लाभ मिले।

लेकिन अग्निपथ योजना में यह प्रक्रिया न तो सुनिश्चित है, न बाध्यकारी। इस कारण अग्निवीरों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक भविष्य दोनों ही अस्थिर बने रहते हैं।

गाजा संकट- इजराइल ने राहत के लिए हर दिन 10 घंटे का 'मानवीय विराम' घोषित किया

एजेंसी

यरुशलम। अंतरराष्ट्रीय दबाव और गाजा में बढ़ते भूख संकट के बीच इजराइली सेना (आईडीएफ) ने रविवार को घोषणा की कि वह गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में हर दिन 10 घंटे के मानवीय विराम का पालन करेगी। इस अवधि के दौरान युद्धक गतिविधियों को स्थगित रखा जाएगा और सुरक्षित रास्तों के माध्यम से खाद्य और दवाओं की आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। आईडीएफ द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह मानवीय विराम सुबह 10 बजे से रात 08 बजे (स्थानीय समयानुसार) तक लागू रहेगा। यह निर्णय अल-मवासी, देइर अल-बलाह और गाजा सिटी जैसे क्षेत्रों में लागू किया जाएगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके अलावा, हर दिन सुबह 06 बजे से रात 11 बजे तक (स्थानीय समयानुसार) संयुक्त राष्ट्र और मानवीय काफिलों के लिए सुरक्षित मार्ग खोले जाएंगे, ताकि राहत सामग्री विशेषकर खाद्य पदार्थ और जीवनरक्षक दवाएं गाजा के जरूरतमंद इलाकों तक पहुंचाई जा सकें। आईडीएफ ने कहा है कि यह निर्णय राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशों और संयुक्त राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के समन्वय में लिया गया है, ताकि गाजा में राहत की मात्रा बढ़ाई जा सके। गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 127 लोगों की भूख और कुपोषण के कारण मौत हो चुकी है, जिनमें 85 बच्चे शामिल हैं।

नेतन्याहू के लिए गले की हड्डी बने हूती, कहा- गाजा पर हमला नहीं रोका तो हर इस्राइली जहाज को उड़ाएंगे

यमन। यमन के हूती विद्रोहियों ने एर्क बार फिर इस्राइल और उसके समर्थन वाले जहाजों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। हूतियों ने साफ कहा है कि अब वे इस्राइलसे जुड़े हर जहाज को अपना निशाना बनाएंगे, चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न हो। यह बयान ऐसे समय आया है जब रेड सी और अरब सागर में पहले ही हूतियों के हमलों से समुद्री परिवहन में रुकावटें आ रही हैं। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने रविवार को एक वीडियो बयान में कहा कि इस्राइल से जुड़े सभी कमर्शियल, तेल या हथियार ले जाने वाले जहाज अब उनके रडार पर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक गाजा पर इस्राइल हमले बंद नहीं होते, तब तक वे अपने 'सैन्य प्रतिरोध' को जारी रखेंगे। इससे पहले भी उन्होंने अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों को चेतावनी दी थी, लेकिन अब उन्होंने अपने दायरे को और बढ़ा दिया है। हूतियों ने यह भी कहा है कि वे उन सभी देशों को भी निशाना बना सकते हैं जो किसी भी रूप में इस्राइल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्राइल हितों की रक्षा करने वाली हर शिपिंग कंपनी या देश उनके निशाने पर रहेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर और गहरा असर पड़ सकता है, खासकर रेड सी और हिंद महासागर के रूट्स पर।

इराक में बंदूकधारियों के हमले में एक सुरक्षाकर्मी सहित दो लोगों की मौत

बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद में कृषि मंत्रालय के कार्यालय पर सशस्त्र बंदूकधारियों के हमले में एक पुलिस जवान और एक नागरिक की मौत हो गयी। इराकी गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि रविवार सुबह नवनियुक्त निदेशक की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक के दौरान बंदूकधारियों के एक समूह ने कार्यालय को निशाना बनाकर गोलीबारी कीइस बीच गोलियों की आवाज सुनकर वहां पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों पर की गयी गोलीबारी में एक जवान की मौत हो गयी और एक अन्य सिविल कर्मचारी मारा गया। इस गोलीबारी में आठ अन्य सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इस सिलसिले में अब तक 14 बंदूकधारियों को हिरासत में लिया गया है। इनकी पहचान इराक के 'पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फोर्सेस (पीएमएफ)' की 45वीं और 46वीं ब्रिगेड के सदस्य के तौर पर की गयी है। इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद सेना के कमांडर-इन- चीफ और प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने मामले की जाँच के लिए एक उच्च-स्तरीय जाँच समिति के गठन का आदेश दिया है।

मिस्र, कतर के विदेश मंत्रियों ने गाजा में मानवीय विकास पर चर्चा की

काहिरा। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती और कतर के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम बिन जाबेर अल थानी ने फोन पर बातचीत कर गाजा पट्टी के हालात और युद्ध विराम सुनिश्चित करने पर चर्चा की। मिस्र के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, चर्चा गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय संकट को कम करने पर केंद्रित थी। दोनों मंत्रियों ने जारी वार्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा व्यापक युद्धविराम समझौते में तेजी लाने की बात की जो गाजा में मानवीय और राहत सहायता की तत्काल आपूर्ति तथा इजरायल की आगे की कार्रवाइयों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने गाजा में युद्ध के बाद पुनरुद्धार एवं पुनर्निर्माण के लिए मिस्र द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित घटनाक्रम पर भी चर्चा की जो युद्धग्रस्त गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए अरब-इस्लामी योजना का हिस्सा है।

पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड का कहर : टीवी एंकर समेत 15 लोग लापता, स्थानीय लोग सरकार की व्यवस्थाओं से नाराज

एजेंसी

पाकिस्तान । पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान में हाईवे पर अचानक पानी भर गया। फ्लैश फ्लड की चपेट में आई एक टीवी एंकर और उसके परिवार के सदस्यों समेत 15 लोगों के बह जाने की आशंका है। वहीं कई दिनों से प्रकृति की मार झेल रहे इस इलाके के विस्थापितों ने स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क पहुंच और संचार सेवाओं की गंभीर कमी की शिकायत की है। बाढ़ से प्रभावित डायमर की बाबूसर और थोर घाटियों में बचे लोगों ने कहा कि वे हाल के दिनों की सबसे घातक बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसमें कई लोग बेघर हो गए और उनका सारा सामान बह गया। मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फ्लैश फ्लड से बाबूसर हाईवे पर अचानक पानी बढ़ गया और इसमें 10 से 15 पर्यटक बह गए। अब तक सात शव बरामद किए जा चुके हैं। पर्यटकों में एक निजी चैनल की टीवी एंकर, उनके पति और उनके चार बच्चे भी शामिल हैं।गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फारक ने बताया

कि एक पश्तो भाषा के टीवी चैनल की एंकर के परिवार ने अधिकारियों से संपर्क कर बताया है कि वह, उनके पति और उनके चार बच्चे लापता हैं। फारक ने बताया कि उन्हें एंकर का एक बटुआ मिला है। वहीं, चिलास के मीनार इलाके में सिंधु नदी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि यह महिला उन पर्यटकों में शामिल है जो बाबूसर हाईवे पर आई बाढ़ में बह गए थे। उन्होंने कहा, खोजी कुत्तों और ड्रोन की मदद से बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने मीडिया को बताया कि भारी मशीनरी का उपयोग करके मरम्मत कार्य जारी है, 15 स्थानों पर सड़क अवरुद्ध है, और उनमें से 13 स्थानों पर आंशिक रूप से मार्ग साफ कर दिया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सोमवार तक राजमार्ग आंशिक रूप से यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। गिलगित क्षेत्र में, दान्योर नाले से आई अचानक बाढ़ के कारण मुख्य आपूर्ति पाइपलाइन और कई सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त होने के बाद, दान्योर और सुल्तानाबाद इलाकों के हजारों निवासी लगातार तीन दिनों तक पीने के पानी के बिना रहे। वहीं आम लोग सरकार की अनदेखी से भी खासा नाराज हैं। गिलगित के पूर्व मंत्री मुहम्मद इकबाल के नेतृत्व में क्षेत्र के बुजुर्गों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार बार-बार आश्वासन के बावजूद बाधित जल आपूर्ति बहाल करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि निवासियों ने पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बहाल करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन बाद में आई बाढ़ ने इसे फिर से नष्ट कर दिया।

सीरिया में असद के पतन के बाद पहली बार संसदीय चुनाव, सितंबर में होंगे मतदान

एजेंसी

दमिश्क। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद सीरिया में पहली बार संसदीय चुनाव की घोषणा की गई है। यह चुनाव 15 से 20 सितंबर 2025 के बीच कराए जाएंगे। इस बात की पुष्टि पीपुल्स असेंबली चुनाव की उच्च समिति के अध्यक्ष मोहम्मद ताहा अल-अहमद ने की, जिनका बयान सरकारी समाचार एजेंसी साना ने जारी किया। यह चुनाव दिसंबर 2024 में बशर अल-असद के शासन के गिरने के बाद स्थापित नई अंतरिम सरकार के अधीन पहली बार होंगे। उस समय सीरिया में एक तेज और अप्रत्याशित विद्रोही हमले में असद शासन का पतन हुआ था। इस नई संसद की रूपरेमा में 210 सदस्य होंगे, जिसमें 70 सदस्य अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शराहा द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। जबकि शेष 140 सदस्य प्रांतवार चुनावी कॉलेजों द्वारा चुने जाएंगे, जैसा कि चुनाव समिति के एक अन्य सदस्य हसन अल-दाघिम ने बताया। मार्च 2025 में हस्ताक्षरित अस्थायी संविधान के अनुसार, यह संसद एक पीपुल्स कमेटी के रूप में कार्य करेगी जब तक कि स्थायी संविधान लागू नहीं हो जाता और आम चुनाव नहीं होते, यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चल सकती है। यह चुनाव उस समय घोषित किए गए हैं जब देश में नए शासकों को लेकर असंतोष और विभाजन गहराता जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में दक्षिणी सूवेदा प्रांत में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस हिंसा की शुरुआत सशस्त्र बेदुईन कबीले और ड्रूज अल्पसंख्यक लड़ाकों के बीच अपहरण की घटनाओं से हुई।

पाकिस्तान में चीन के इंजीनियरों पर हमला करने वाले टीटीपी के तीन आतंकी मारे गए

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अधिकारियों ने पिछले साल नवंबर में चीन के इंजीनियरों पर हुए हमले में शामिल प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के तीन आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। तीनों को आज सुबह कराची के मंघोपीर इलाके में आतंकवाद-रोधी अभियान के दौरान मार गिराया गया। डान अखबार के अनुसार आतंकवाद निरोधी विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक आजाद खान ने कहा कि चीन के इंजीनियरों पर हमले का मास्टर माइंड जफरान अपने दो साथियों के साथ कराची के मंघोपीर इलाके के एक घर में छुपा था। खुफिया एजेंसियों के कर्मियों और आतंकवाद-रोधी अभियान में शामिल जवानों ने तीनों को घेरकर मौत के घाट उतार दिया। इस अधिकारी के अनुसार चीन के इंजीनियरों को पिछले साल पांच नवंबर को कराची की एक कपड़ा मिल में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने गोली मारकर घायल कर दिया था। जांचकर्ताओं को संदेह था कि यह लक्षित आतंकी हमला है। इस घटना के बाद भागे निजी सुरक्षा गार्ड के

खिलाफ दो दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। तत्कालीन डीआईजी (दक्षिण) सैयद असद रजा ने बताया कि एक सुपरवाइजर और तीन गार्डों ने पूछताछ में यह कबूल किया था कि हमले का मास्टरमाइंड टीटीपी का जफरान है। दरअसल, नवंबर, 2022 में टीटीपी के सरकार के साथ युद्धविराम समाप्त करने के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2024 तक मुल्क में हुए आतंकवादी हमलों में 20 चीनी नागरिक मारे गए और 34 घायल हुए।

चीन में भूस्खलन से चार की मौत, आठ लापता, बीजिंग बाढ़ की चपेट में

एजेंसी

बीजिंग। चीन में मूसलाधार बरसात ने बड़े हिस्से में तबाही मचाई है। अधिकांश नदी-नाले उफान पर हैं। इस बीच उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत के एक गांव में सोमवार तड़के हुए भूस्खलन में चार लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य लापता हैं। ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि चेंगडे शहर के लुआनपिंग काउंटी स्थित गांव में भारी बारिश के बीच भूस्खलन हुआ। बचाव कार्य जारी है। इसके अलावा राजधानी बीजिंग और हेबेई प्रांत सहित उत्तरी चीन के कई क्षेत्र मूसलाधार बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। नगरपालिका अधिकारियों के अनुसार, बीजिंग में सोमवार को बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी दी गई कि यानकिंग, हुआइरौ और मियुन आदि जिलों के पहाड़ी इलाकों में सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।राष्ट्रीय विकास और सुधार

आयोग ने हेबेई प्रांत में स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय बजट से 50 मिलियन युआन (6.97 मिलियन डॉलर) का आवंटन किया है। बीजिंग में आज खेलकूद गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। बीजिंग आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो ने कहा कि चाओबाई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार सुबह 10 बजे तक शहर के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होगी। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन खतरा बहुत अधिक है। देश में शनिवार से हुई लगातार बारिश के कारण हेबेई, बीजिंग, इनर मंगोलिया, शांक्सी, शानक्सी, युन्नान और शिनजियांग की 31 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

किम जोंग-उन की बहन ने किया स्पष्ट, 'दक्षिण कोरिया से बातचीत में हमें कोई दिलचस्पी नहीं'

एजेंसी

सोल । उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की बहन किम यो-जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की किसी भी नीति या प्रस्ताव में रुचि नहीं रखता और न ही सोल के साथ किसी तरह की बातचीत के लिए तैयार है।

सत्तारूढ़ पार्टी की केंद्रीय समिति की उप निदेशक किम यो-जोंग का यह बयान कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने जारी किया है। यह बयान दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्युंग के उस प्रयास के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने सैन्य तनाव कम करने और दोनों कोरियाई देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए बातचीत की पेशकश की थी। यह उत्तर कोरिया का ली प्रशासन पर पहला आधिकारिक बयान है, जो पिछले महीने सत्ता में आया। किम

यो-जोंग ने कहा, ली जे म्युंग के पिछले 50 दिनों के शासन को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि वह अपने पूर्ववर्ती से अलग नहीं हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया-अमेरिका गठबंधन को बेतहाशा समर्थन देने और उत्तर कोरिया के साथ टकराव की नीति अपनाने का आरोप लगाया। किम ने आगे कहा, दक्षिण कोरिया चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उत्तर कोरिया का रुख नहीं बदलेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया, हम दक्षिण कोरिया के किसी भी प्रस्ताव या नीति में रुचि नहीं रखते और न ही उनके साथ बातचीत के लिए बैठेंगे। किम ने दक्षिण कोरिया के उस प्रस्ताव की भी आलोचना की, जिसमें अंतर-कोरियाई मामलों के लिए जिम्मेदार एकीकरण मंत्रालय को सामान्य करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा, दोनों कोरिया अलग-अलग देश हैं, इसलिए इस मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए। किम ने दक्षिण कोरिया पर एकीकरण द्वारा अवशोषण की भ्रांति में होने का आरोप लगाया। किम ने यह भी कहा कि अगर दक्षिण कोरिया को लगता है कि कुछ भावनात्मक शब्दों से वह अपने पिछले कार्यों के परिणामों को बदल सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। उन्होंने उत्तर कोरिया को मुख्य दुश्मन घोषित करने और टकराव की नीति अपनाने के लिए सोल की आलोचना की। साथ ही एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) शिखर सम्मेलन में किम जोंग-उन को आमंत्रित करने के दक्षिण कोरिया के प्रस्ताव को हास्यास्पद भ्रम करार दिया। ये सम्मेलन अक्टूबर में ग्योंगजू में होने वाला है।

जर्मनी में ट्रेन के पटरी से उतरने से तीन लोगों की मौत, कई घायल

एजेंसी

बर्लिन। दक्षिणी जर्मन राज्य बाडेन-वुर्टेमबर्ग में एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी। यह दुर्घटना रीडलिंगन शहर के पास उस समय हुई जब ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। पुलिस के एक बयान के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर एक कमांड सेंटर स्थापित किया है और बचाव कर्मियों को तैनात किया है। प्रभावित रेलवे लाइन और पास की सड़क को बंद कर दिया गया है। बयान के अनुसार, ट्रेन की पटरी से उतरने के कारणों की जांच चल रही है।जर्मन प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह इलाका पहले भी तूफ़ान की चपेट में आ चुका है।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पीड़ितों के प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

'जुलाई चार्टर' पर फेल अंतरिम सरकार, एनसीपी ने दी विरोध की चेतावनी

एजेंसी

ढाका । बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के संयोजक नाहिद इस्लाम ने धमकी दी है कि अगर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार 5 अगस्त तक 'जुलाई चार्टर' की घोषणा नहीं करती है, तो वह ढाका के 'सेंट्रल शहीद मीनार' पर धरना देंगे। पार्टी की शेरपुर जिला इकाई ने एक रैली का आयोजन किया, जिसे संबोधित करते हुए नाहिद ने कहा, ÷हम 3 अगस्त को ढाका लौटेंगे। हम अपनी मांग (जुलाई चार्टर के लिए) पूरी किए बिना शहीद मीनार (परिसर) नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, लगभग एक साल बीत चुका है, फिर भी अंतरिम सरकार जुलाई चार्टर तैयार करने में नाकाम रही है। अब हम सुन रहे हैं कि कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है,

लेकिन अगर बुनियादी सुधार नहीं किए गए और उन्हें जुलाई चार्टर में शामिल नहीं किया गया, तो एनसीपी चार्टर का समर्थन नहीं करेगी। एनसीपी पार्टी की मांग दोहराते हुए नाहिद ने संसद में एक उच्च सदन के गठन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) प्रणाली के तहत चुनाव कराने की मांग की।बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने नए सुधार ढांचे में प्रधानमंत्री की शक्तियों को सीमित करने की भी मांग की। पिछले महीने, देश में राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता के जारी रहने के बीच, 30 राजनीतिक दलों और बांग्लादेश के नेशनल कन्सेंसस कमीशन (एनसीसी) के बीच दूसरे चरण की चर्चा शुरू हुई थी। इस वार्ता का उद्देश्य अंतरिम सरकार की ओर से गठित विभिन्न सुधार आयोगों की सिफारिशों को पूरा करना और जुलाई चार्टर का मसौदा तैयार करना था। दूसरे दौर की बातचीत के दौरान, एनसीसी राजनीतिक दलों के बीच विवादों के बीच प्रमुख सुधारों पर आम सहमति बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। जो पार्टियां छात्र नेताओं और यूनुस के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई अवामी लीग सरकार को गिराने के लिए एकजुट हुई थीं, वे अब सार्वजनिक रैलियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक-दूसरे के खिलाफ हमलावर हो रही हैं।

थाईलैंड के कंमाडर बूनसिन पैडक्लांग अग्रिम मोर्चे पर, कहा-कंबोडिया ने मौत की अफवाह फैलाई

एजेंसी

बैंकॉक। थाईलैंड की सेकेंड आर्मी एरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बूनसिन पैडक्लांग ने अपनी मौत की खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर अपने सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं। कमांडर पैडक्लांग ने आज कहा कि कंबोडिया ने अफवाह फैलाकर थाई सैनिकों का मनोबल गिराने की कोशिश की है कि वह कंबोडियाई बलों के हाथों मारे गए हैं। थाईलैंड के अखबार द नेशन की खबर के अनुसार, बूनसिन ने कहा कि कंबोडिया ने तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ की है। उन्होंने कहा, मैं अभी भी सीमा पर हूं। अपने लोगों की सुरक्षा के लिए थाई-कंबोडियाई सीमा क्षेत्र में थाई सैनिकों के साथ लड़ रहा हूं। मैं तब तक देश की संप्रभुता की रक्षा करता रहूंगा जब

तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। इस बीच थाई सशस्त्र बलों के प्रवक्ता मेजर जनरल विथाई लैथोम्य ने कंबोडिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेता के दावों का खंडन किया है। सोचेता ने थाईलैंड पर कंबोडियाई की संप्रभुता का उल्लंघन करने और बिना उकसावे के हमले करने का आरोप लगाया था। विथाई ने आरोपों को निराधार और झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। सुरीन के गवर्नर चमन चुएंटा ने प्रभावित नागरिकों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रांत को युद्ध आपदा क्षेत्र घोषित किया है। चुएंटा ने सभी जिला प्रमुखों, प्रांतीय प्रशासनिक संगठन के अध्यक्ष और सूरीन नगर पालिका के महापौर को सीमा पर बढ़ती हिंसा के मद्देनजर एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि सुरिन प्रांत को युद्ध आपदा क्षेत्र घोषित किया जाता है।

दक्षिण अफगानिस्तान में हथियारों का जखीरा बरामद, दो गिरफ्तार

एजेंसी

काबुल। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने देश के दक्षिणी प्रांत उरुजगान में एक बड़े हथियार और गोला-बारूद के भंडार का खुलासा किया है। इस दौरान दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि त्रिन कोट शहर में की गई एक खुफिया कार्रवाई के दौरान यह जब्ती की गई। बयान में कहा गया है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने उरुजगान प्रांत की राजधानी त्रिन कोट में अभियान चलाया, जिसमें उन्हें भारी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण मिले। सुरक्षा बलों द्वारा बरामद किए गए हथियारों में छह एके-47 राइफलें, एक भारी मशीन गन, पीके मशीन गनें, रॉकेट लॉन्चर और सैकड़ों हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और सैन्य साजोसामान भी जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और आशंका है कि इस मामले का संबंध आतंकी या अस्थिरकारी गतिविधियों से हो सकता है। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार पिछले साढ़े तीन वर्षों से देशभर में सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से अवैध हथियारों और गोला-बारूद के जखीरे को जब्त करने की व्यापक मुहिम चला रही है। अब तक हजारों हथियार और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की जा चुकी है।

'भूख से हो रही मौतें रुकनी चाहिए', पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहली बार गाजा युद्ध पर किया पोस्ट

एजेंसी

शिकागो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गाजा में लड़ाई शुरू होने के बाद सोमवार को पहली बार गाजा युद्ध पर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की। बराक ओबामा ने गाजा में भुखमरी के हालात पर चिंता जताई और इसे तुरंत खत्म करने की अपील की। बराक ओबामा ने कहा कि गाजा में मासूम लोगों की मौतों को रोका जाना चाहिए। जो अमेरिका खुलकर इस्राइल के समर्थन में है, उसके पूर्व राष्ट्रपति का यह बयान बेशक इस्राइल पर दबाव को बढ़ाएगा।

ओबामा बोले- आम नागरिकों का खाना और पानी रोकना गलत

बराक ओबामा ने एक अमेरिकी अखबार में लेख लिखा। इस लेख के लिंक को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए एक पोस्ट में ओबामा ने लिखा कि 'गाजा संकट के समाधान में सभी बंधकों की वापसी और इस्राइली सेना की सैन्य कार्रवाई की समाप्ति होनी ही चाहिए, लेकिन इस लेख में गाजा में भूख से हो रही, रोकी जा सकने वाली मौतों को तुरंत रोकने की जरूरत को उल्लेखित किया गया है।' ओबामा ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि 'गाजा में मदद को लोगों तक पहुंचने की इजाजत जरूर दी जानी चाहिए। आम नागरिकों का खाना और पानी रोकने के किसी भी तर्क को सही नहीं ठहराया जा सकता।'

इस साल गाजा में कुपोषण से 74 लोगों की मौत हुई

गाजा को इस्राइल द्वारा ब्लॉक

किया गया है, जिसके चलते गाजा में मानवीय मदद नहीं पहुंच पा रही है। इसके कारण गाजा में भुखमरी फैल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को चेतावनी दी कि गाजा में कुपोषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि यह भुखमरी पूरी तरह से रोकी जा सकती है और इसके चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। डब्लूएचओ ने बताया कि इस साल गाजा में 74 लोगों की मौत कुपोषण संबंधी कारणों से हुई है। इनमें से 63 लोगों की जान तो जुलाई में ही गई है। इनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं, जो पांच साल से कम उम्र के थे। डब्लूएचओ का कहना है कि गाजा में हर पांच बच्चों में से एक कुपोषण का शिकार है। जून के महीने से गाजा में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा तीन गुना बढ़ चुका है। इस्राइल का आरोप है कि गाजा में पहुंचने वाली हर मानवीय मदद को हमास द्वारा जब्त कर लिया जाता है। मानवीय मदद पर इस्राइल की रोक को हमास पर बातचीत शुरू करने के

डायग्नोस्टिक सेंटर व्यापार नहीं, सेवा का माध्यम है : नितिन गडकरी

एजेंसी

मुंबई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर व्यापार नहीं, सेवा का माध्यम है। समाज के वंचितों और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की सेवा करने का अंत्योदय का विचार पं. दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। उसी मार्ग पर मैं लगातार कार्य कर रहा हूं। नितिन गडकरी नागपुर के लष्करीबाग में स्थित कमाल चौक पर स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण, समाजसेवा और जनसेवा - यही राजनीति का सच्चा अर्थ है। अपने कार्यों के माध्यम से गरीबों का जीवन कैसे बदला जा सकता है, इस पर मैं विचार करता हूं। इसी प्रेरणा से और अनेक लोगों के सहयोग से स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना संभव हो पाई। जिस मां ने जन्म दिया, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह अवसर मुझे मिला - इसका संतोष मुझे है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से हर तीन किलोमीटर पर स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अगले चार वर्षों में महाराष्ट्र में देश की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित की जाएगी।

अदाणी ग्रीन का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 824 करोड़ रुपये रहा

नई दिल्ली। अदाणी ग्रीन शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 824 करोड़ रुपये दर्ज हुआ। यह पिछले वर्ष 629 करोड़ रुपये था। वहीं इस वर्ष 31 प्रतिशत अधिक राजस्व 3800 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वर्ष 2794 करोड़ रुपये दर्ज हुआ था। एबिटा 36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,042 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 2379 करोड़ रुपये था। साथ ही मार्जिन 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80 प्रतिशत दर्ज हुआ।

ब्रिटेन के साथ एफटीए के पहले साल भारत को होगा 4060 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान, जीटीआरआई का दावा

नई दिल्ली। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के पहले वर्ष में भारत को 4,060 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क राजस्व का नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क कम या समाप्त कर दिया गया है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने सोमवार को ब्रिटेन से वर्तमान आयात आंकड़ों का हवाला देकर यह बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 वर्ष तक, जैसे-जैसे टैरिफ उन्मूलन चरणबद्ध तरीके से व्यापक रूप से लागू होगा, वित्त वर्ष 2025 के व्यापार की मात्रा के आधार पर वार्षिक घाटा बढ़कर 6,345 करोड़ रुपये या लगभग 574 मिलियन ब्रिटिश पाउंड तक पहुंचने का अनुमान है। जीटीआरआई ने कहा है कि 24 जुलाई को हस्ताक्षरित भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के सीमा शुल्क राजस्व में कमी आएगी, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क कम कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है। भारत ने 2024-25 में ब्रिटेन से 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सामान आयात किया। इन आयातों में औद्योगिक उत्पादों का बड़ा हिस्सा शामिल है और इन पर 9.2 प्रतिशत का भारित औसत टैरिफ लगता है। व्हिस्की और जिन जैसी वस्तुओं को छोड़कर, अधिकांश कृषि उत्पादों को, जिन पर 64.3 प्रतिशत का बहुत अधिक औसत टैरिफ लगता है, टैरिफ कटौती से बाहर रखा गया है। इसमें कहा गया है कि भारत ने ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं के मूल्य के 64 प्रतिशत पर टैरिफ को तत्काल समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकों का भरोसा कायम

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने 36,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की। आरबीआई ने 5.91 फीसदी पर 2028 में परिपक्व होने वाली प्रतिभूति के लिए 6,000 करोड़ रुपये और 6.33 फीसदी पर 2035 में परिपक्व होने वाली प्रतिभूति के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि तय की थी। दोनों नीलामियां पूरी तरह सब्सक्राइब हो गईं। यह सरकारी बॉन्ड के प्रति निवेशकों की मजबूत मांग को दर्शाता है। आंकड़ों के अनुसार 5.91 प्रतिशत जीएस 2028 के लिए 98 प्रतिभागियों से कुल 24,453 करोड़ रुपये के प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्ताव मिले। वहीं, 6.33 प्रतिशत जीएस 2035 के लिए 402 बोलियों के जरिए 74,694 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं। मूल्यांकन के बाद, आरबीआई ने 2028 बॉन्ड के लिए 5,998.13 करोड़ रुपये और 2035 बॉन्ड के लिए 29,947.86 करोड़ रुपये की प्रतिस्पर्धी बोलियों को स्वीकार किया। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां भी पूरी तरह स्वीकार कर ली गईं। इनकी राशि क्रमशः 1.86 करोड़ रुपये और 52.13 करोड़ रुपये थी।

अमेरिका, यूरोपीय संघ में हुआ व्यापार समझौता

एजेंसी

लंदन। अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) में व्यापार को लेकर सहमति बन गई है। दोनों ने एक बैठक के बाद तय किया कि अमेरिका, ईयू के कई उत्पादों पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने हुई बैठक के बाद यह एलान किया। यह घोषणा स्कॉटलैंड में हुई बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। दोनों नेताओं ने इस समझौते को 'व्यापार संतुलन' बहाल करने और अधिक न्यायसंगत कारोबार को बढ़ावा देने वाला बताया। श्री ट्रंप ने प्रेस वार्ता में, दावा किया कि यह समझौता अमेरिकी कारों को यूरोपीय बाजार में दोबारा प्रवेश करने और ईयू में कृषि निर्यात को सरल बनाएगा। दवाईयां इस समझौते से बाहर हैं, जबकि ईयू से अमेरिका को निर्यात होने वाले स्टील और एल्युमीनियम पर मौजूदा 50 प्रतिशत शुल्क लागू रहेंगे। विदित हो कि इससे पहले तक ईयू से अमेरिका को निर्यात होने वाली कारों पर पहले ढाई प्रतिशत टैक्स था जो अब

बढ़कर 15 फीसदी हो जाएगा। यह समझौता अमेरिका को ईयू उत्पादों पर व्यापक रूप से 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की बात कहता है। साथ ही इसमें कई अमेरिकी निर्यातों के लिए शून्य- आयात शुल्क की भी बात है। यही नहीं ईयू 750 अरब डॉलर मूल्य की अमेरिकी ऊर्जा खरीदने और अमेरिका में 600 अरब डॉलर के निवेश की भी बात कही है।

एक अलग प्रेस वार्ता में, सुश्री लेयेन ने स्पष्ट किया कि ईयू और अमेरिका दवाइयों को 15 प्रतिशत शुल्क ढांचे में शामिल करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने भविष्य में अमेरिका के और अधिक व्यापारिक कदम उठाने की संभावना से इनकार नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या इससे यूरोपीय कार निर्माताओं को नुकसान नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि वास्तव में कारों पर ढाई प्रतिशत के अलावा 25 प्रतिशत का अन्य कर भी लगता है। तो अब नई दर वास्तव में कर में कमी को दर्शाती है, लेकिन इस समझौते से सब लोग सहमत नहीं हैं।

यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्न्ड लैंग ने इस नए समझौते की आलोचना करते हुए इसे 'असंतोषजनक' और 'काफी असंतुलित' बताया और चेतावनी दी कि यह ईयू की आर्थिक स्थिरता और रोज़गार सुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है। श्री लैंग ने एक बयान में कहा, यह एक पक्षपातपूर्ण समझौता है। स्पष्ट रूप से, इसमें ऐसी रियायतें दी गई हैं जिन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल है। विदित हो कि श्री ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि अगर एक अगस्त तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका अभी जो 10 प्रतिशत शुल्क लगाता है उसको बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

एसबीआई की नई 'हर घर लखपति' आरडी योजना

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपनी एक नई रिकरिंग डिपॉजिट योजना, 'हर घर लखपति', लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य आम लोगों को नियमित और छोटे निवेश के माध्यम से एक बड़ी राशि जमा करने में मदद करना है। यह योजना उन लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हैं और भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस नई ऋष्ठ योजना के माध्यम से, SBI अपने ग्राहकों को एक अनुशासित निवेश पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है ताकि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकें। 'हर घर लखपति' SBI योजना निवेशकों को कम निवेश से शुरुआत करने और आकर्षक ब्याज दरों का लाभ उठाने का मौका देती है। बैंक ने इस योजना को विशेष रूप से ऐसे ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया है जो एक निश्चित अवधि में एक बड़ी राशि (जैसे ?1 करोड़ या उससे अधिक) जमा करना चाहते हैं। इसमें निवेशक अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार मासिक किश्तें जमा कर सकते हैं।

इस योजना से न केवल अनुशासित बचत को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह निवेशकों को लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ भी देगी, जिससे वे अपनी निवेशित राशि को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और हर भारतीय को 'लखपति' बनने के सपने को साकार करने में मदद करेगी।

स्टॉक मार्केट में स्वास्तिका कैस्टल की फीकी एंट्री

एजेंसी

नई दिल्ली। एल्यूमीनियम कास्टिंग बनाने वाली कंपनी स्वास्तिक कैस्टल के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मामूली बढ़त के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 65 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 3.08 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 67 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद भी इस शेयर में कोई खास हलचल नहीं हो रही है। सुबह 10.15 बजे तक का कारोबार होने के बाद भी कंपनी के शेयर 67 रुपये के स्तर पर ही बने हुए थे। स्वास्तिक कैस्टल का 14.07 करोड़ रुपये का आईपीओ 21 से 23 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 5.08 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 7.75 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस

आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 21.64 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नई मशीनरी खरीदने, नया शेड और बिल्डिंग बनाने, अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 58 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 65 लाख रुपये और 2024-25 में उछल कर 2.63 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी के राजस्व में उतार चढ़ाव होता रहा। 2022-23 में कंपनी को 24.41 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो 2023-24 में घटकर 23.35 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि 2024-25 में इसके राजस्व में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण ये उछल कर 30.31 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

देश की टॉप 6 कंपनियों का मार्केट कैप 2.22 लाख करोड़ से ज्यादा गिरा, चार कंपनियां को फायदा

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में पिछले कारोबारी सप्ताह के दौरान हुई खरीद-बिक्री के कारण देश की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड कंपनियों में से 6 कंपनियों के मार्केट कैप में 2.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इनमें सबसे अधिक नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ। दूसरी ओर, टॉप 10 में शामिल 4 कंपनी के मार्केट कैप में इस सप्ताह 1.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। इनमें सबसे अधिक फायदा एचडीएफसी बैंक को हुआ। इस सप्ताह के कारोबार के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिन्दुस्तान यूनिलीवर और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मार्केट कैप में 2,22,193.17 करोड़ रुपये की गिरावट आ गई। दूसरी ओर, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के मार्केट कैप में 1,03,502.48 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। दौरान इस 21 से 25 जुलाई के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 1,14,687.70 करोड़ रुपये लुढ़क कर 18,83,855.52 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इसी तरह इंफोसिस का मार्केट कैप 29,474.56 करोड़ रुपये कम होकर 6,29,621.56 करोड़ रुपये के स्तर तक गिर गया। इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मार्केट कैप 23,086.24 करोड़ रुपये के नुकसान के साथ 5,60,742.67 करोड़ रुपये के स्तर पर, टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का मार्केट कैप 20,080.39 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ 11,34,035.26 करोड़ रुपये के स्तर पर, बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 17,524.30 करोड़ रुपये की कमजोरी के साथ 5,67,768.53 करोड़ रुपये के स्तर पर और हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप 17,339.98 करोड़ रुपये कम होकर 5,67,449.79 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। दूसरी ओर, एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 37,161.53 करोड़ रुपये की उछाल के साथ 15,38,078.95 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 35,814.41 करोड़ रुपये बढ़ कर 10,53,823.14 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा भारती एयरटेल का मार्केट कैप 20,841.20 करोड़ रुपये उछल कर 11,04,839.93 करोड़ रुपये के स्तर पर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का मार्केट कैप 9,685.34 करोड़ रुपये बढ़ कर 7,44,449.31 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

सेवी इंफ्रा की स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री, फायदे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। नए प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन तैयार करने वाली कंपनी सेवी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूती के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 120 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 13.75 प्रतिशत प्रीमियम के साथ इसकी लिस्टिंग 136.50 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद खरीदारी के सपोर्ट से कंपनी के शेयरों को और मजबूती मिली। सुबह 11 बजे तक का कारोबार होने के बाद भी कंपनी के शेयर 143 रुपये के स्तर पर पहुंचे हुए थे। इस तरह शुरुआती डेढ़ घंटे के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 19.17 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है। सेवी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स का 69.98 करोड़ रुपये का आईपीओ 21 से 23

जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 114.50 गुना सब्सक्राइब हो गया था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 93.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 196.44 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 91.62 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 58.32 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 34 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 9.87 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 23.88 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी के राजस्व में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। 2022-23 में कंपनी को 6.19 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो 2023-24 में बढ़ कर 101.62 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 238.77 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

पर्यटन को नई उड़ान, टूरिज्म कॉन्क्लेव में मप्र को मिले 3000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

एजेंसी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रीवा रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में पर्यटन क्षेत्र के लिए एक नई सुबह का आगाज हुआ है। आज पर्यटन श्रेत्र में प्रमुख निवेशकों ने रीवा और शहडोल संभाग में तीन हजार करोड़ से अधिक के निवेश की इच्छा जताकर इन क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया है। यह ऐतिहासिक पल दोनों संभागों के लिए आर्थिक समृद्धि और रोजगार के नए द्वार खोलेगा। कॉन्क्लेव में निवेशकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार की शाम रीवा में आयोजित दो दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव के शुभारंभ कार्यक्रम में पर्यटन क्षेत्र के निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन कर इस दो दिवसीय रीजनल कान्क्लेव का विधिवत शुभारंभ किया। यह कान्क्लेव 27 जुलाई को भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास के मायने तभी हैं, जब हम अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति और अपनी विरासतों से भी आत्मीयता से जुड़े रहें। हम विरासत से विकास की ओर मिशन मोड में आगे बढ़ रहे हैं। विंध्य क्षेत्र हमेशा से ही मध्य प्रदेश का गौरव रहा है। इस क्षेत्र के विकास में अब कोई भी बाधा नहीं रही। हम यहां की हेरिटेज साइट्स को समुचित तरीके से सहेजकर पूरे विंध्याचल को उसका पुरा वैभव लौटाएंगे।

सर्राफा बाजार में मामूली गिरावट, सोना और चांदी की घटी कीमत

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज लगातार पांचवें दिन गिरावट का रुख बना हुआ है। हालांकि आज की गिरावट काफी मामूली है। कीमत में गिरावट आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 99,920 रुपये से लेकर 1,00,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 91,590 रुपये से लेकर 91,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी मामूली कमजोरी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,15,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,00,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 91,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई

में 24 कैरेट सोना 99,920 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 91,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 99,970 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,640 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 99,920 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 91,590 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 99,920 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 91,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,00,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 91,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 91,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,00,070 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 91,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोना सस्ता हुआ है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 99,920 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 91,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी की अटकलों पर वित्त राज्य मंत्री का बड़ा अपडेट

एजेंसी

नई दिल्ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाए जाने की अटकलों पर आज वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने की कोई योजना नहीं है। उनके इस बयान से उन अफवाहों पर विराम लग गया है, जो पिछले कुछ समय से ऑनलाइन भुगतान करने वाले लाखों भारतीयों के बीच चिंता का विषय बनी हुई थीं। यह घोषणा वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश में डिजिटल भुगतान को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार

प्रयासरत है, और UPI इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। UPI ने भारत में डिजिटल लेनदेन में क्रांति ला दी है और करोड़ों लोगों के लिए भुगतान को आसान बनाया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस डिजिटल क्रांति को जारी रखा जाए और आम जनता पर अनावश्यक बोझ न डाला जाए। यह स्पष्टीकरण उन सभी अटकलों को खारिज करता है, जिनमें UPI लेनदेन पर कर लगाए जाने की संभावना जताई जा रही थी, जिससे डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में विश्वास और बढ़ेगा।

ब्यूटी और पर्सनल केयर ई-कॉमर्स मार्केट में तेजी

एजेंसी

मुंबई। वैश्विक सौंदर्य और पर्सनल केयर ई-कॉमर्स बाजार अगले पांच वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। डिजिटल एंड ट्रेंड्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और 2029 तक इसमें निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 2018 में, इसका कुल बाजार राजस्व 115.23 डॉलर था। यह संख्या पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है। 2019 में, इसका राजस्व बढ़कर 132.6 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। साल 2020 में यह और बढ़कर 166.06 अरब डॉलर हो गया। 2021 में भी वृद्धि जारी रही और 201.66 अरब डॉलर तक पहुंच गई। हालांकि 2022 में इसमें मामूली गिरावट आई और यह 196.56 अरब डॉलर पर आ गया। लेकिन बाजार में तेजी से सुधार हुआ और 2024 में यह 227.26 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रिपोर्ट में 2025 के लिए 257.54 अरब डॉलर के राजस्व का अनुमान लगाया है। 2028 में 327.22 डॉलर के राजस्व के साथ यह वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2029 तक बाजार 338.93 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह 2024 के स्तर से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खंडवार सबसे बड़ा योगदान पर्सनल केयर से आता है। इसके बाद कॉस्मेटिक, स्किनकेयर, फ्रेगरेंस और ब्यूटी टेक सेगमेंट आते हैं। आंकड़ों के अनुसार, पर्सनल केयर सेगमेंट हर साल बाजार में सबसे अधिक हिस्सेदारी बनाए रखता है, जबकि ब्यूटी टेक सबसे छोटा सेगमेंट है।

जैविक कपास की खेती पर कथित सरकारी सब्सिडी में घोटाले और प्रमाणन का एपीडा ने किया खंडन

एजेंसी

नई दिल्ली। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने जैविक कपास की खेती पर कथित सरकारी सब्सिडी में घोटाला और जैविक प्रमाणन में गड़बड़ी के आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया है। एपीडा ने कहा कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत जैविक प्रमाणन में तीसरे पक्ष का प्रमाणन शामिल है, जिसे फसल स्तर पर यूरोपीय आयोग और स्विट्जरलैंड द्वारा मान्यता प्राप्त है।उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को जैविक कपास की प्रामाणिकता की कुछ पश्चिमी बाजारों में अस्वीकार्यता को लेकर बयान दिया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही इस एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) 2001 में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा जैविक उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु शुरू किया गया था और एपीडा एनपीओपी के कार्यान्वयन हेतु सचिवालय के रूप में कार्य करता है। उत्पादक समूह प्रमाणन प्रणाली 2005 में शुरू की गई थी, क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे आवश्यक समझा गया था। जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए तृतीय पक्ष प्रमाणन अनिवार्य है। फसल उत्पादन के लिए एनपीओपी मानकों को यूरोपीय आयोग और स्विट्जरलैंड द्वारा अपने देश के मानकों के समकक्ष मान्यता दी गई है और ब्रिटेन ने भी इसे स्वीकार किया है। ताइवान के साथ जैविक उत्पादों के लिए भी एक समझौता है। बयान में कहा गया है कि एनपीओपी के तहत जैविक प्रमाणन प्रणाली में जैविक प्रक्रियाओं और जैविक उत्पादों के लिए एक तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्रणाली शामिल है, जिसे एक प्रमाणन निकाय (सरकारी या निजी) द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में प्रमाणित किया जाता है। मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय अपनी मान्यता के दायरे के अनुसार जैविक संचालकों को प्रमाणित करते हैं। वर्तमान में, भारत में 37 सक्रिय प्रमाणन निकाय कार्यरत हैं, जिनमें 14 राज्य प्रमाणन निकाय शामिल हैं। एपीडा ने स्पष्ट किया जाता है कि एपीडा या वाणिज्य विभाग, एनपीओपी के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को कोई सब्सिडी नहीं देता है। 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का आँकड़ा और अन्य गलत गणनाएँ निराधार हैं। एनपीओपी के तहत जैविक प्रमाणीकरण केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार, एनपीओपी के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा प्रमाणित लगभग 19,29,243 किसानों को कवर करने वाले 4712 सक्रिय जैविक उत्पादक समूह हैं। ये उत्पादक समूह अनाज, दलहन, तिलहन, चाय, कॉफी, मसालों और केवल कपास सहित विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन में शामिल हैं। इस प्रकार, ब्रीफिंग में उल्लिखित जैविक उत्पादक समूहों की संख्या किसानों की संख्या के साथ गलत है, यह अनुमान लगाना भी भ्रामक है कि भारत के सभी जैविक उत्पादक समूह मध्य प्रदेश में स्थित हैं और केवल कपास का उत्पादन कर रहे हैं। गौरतलब है कि कपास केवल उत्पादन स्तर तक ही एनपीओपी के अंतर्गत आता है। इसके बाद, ओटाई, प्रसंस्करण आदि सहित उत्पादनोत्तर कार्य निजी प्रमाणीकरण के अंतर्गत किया जाता है। एनपीओपी के अंतर्गत, आईसीएस का प्रबंधन स्वयं किया जा सकता है या किसी सेवा प्रदाता/अधिदेशक के माध्यम से किया जा सकता है। एनपीओपी मानकों के अनुसार, आईसीएस के लिए सभी किसानों का वर्ष में दो बार आंतरिक निरीक्षण करना अनिवार्य है।

वो एक्ट्रेस, जिसने ठुकरा दी थी 'सैयारा' के डायरेक्टर की फिल्म, चमक उठी थी

श्रद्धा कपूर

की किस्मत

सैयारा के डायरेक्टर मोहित सूरी कुछ साल पहले हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से एक फिल्म लेकर आए थे. श्रद्धा कपूर उस फिल्म में लीड रोल में थीं, लेकिन वो उस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थीं.

इन दिनों हर तरफ सिर्फ एक ही फिल्म छाई हुई है. 'सैयारा', जिसमें अनीत पड्डा और अहान पांडे लीड रोल में नजर आए हैं. फिल्म ने 8 दिनों में दुनियाभर में 281 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है. मोहित सूरी वही डायरेक्टर हैं, जिन्होंने साल 2017 में हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से फिल्म बनाई थी.मोहित ने 'हाफ गर्लफ्रेंड' में अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर को लीड रोल में लिया था. हालांकि, मेकर्स श्रद्धा से पहले किसी दूसरी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी थी. वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि कृति सेनन हैं.

नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी हैं कृति सेनन

आज यानी 27 जुलाई को कृति सेनन का 35वां जन्मदिन है. वो पिछले 11 सालों से बॉलीवुड में काम कर रही हैं. अब तक उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. वो 'मिमी' फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं. हाफ गर्लफ्रेंड के मेकर्स अर्जुन के साथ कृति को कास्ट करना चाहते थे. कृति उस समय किसी दूसरी फिल्म पर काम कर रही थीं, जिस वजह से उन्होंने मोहित सूरी की फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था.

सुशांत के साथ साइन कर ली थी फिल्म

हाफ गर्लफ्रेंड का ऑफर मिलने से पहले ही कृति सेनन ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक फिल्म साइन कर ली थी. वो उसी फिल्म पर अपना 100 प्रतिशत देना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड के लिए मना कर दिया था. उसके बाद श्रद्धा कपूर को कास्ट किया गया था, जो पहले मोहित सूरी के ही डायरेक्शन में बनी फिल्म 'आशिकी 2' में काम कर चुकी थीं.

इस फिल्म से शुरू किया था करियर

कृति सेनन ने अपना फिल्मी करियर साल 2014 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म 'नेनोक्कडीने' से शुरू किया था. उसी साल उनकी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म रिलीज हुई थी. नाम 'हीरोपंती', जिसमें उनके साथ टाइगर श्रॉफ नजर आए थे. शब्बीर खान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के सामने टिक पाएगी 'अनुपमा'? हितेन तेजवानी बोले- किसी को नीचा दिखाने...

टीवी की पॉपुलर प्रोड्यूसर एकता कपूर साल 2000 में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' लेकर आई थीं जो 2008 तक स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ. लगभग 8 सालों तक इस सीरियल ने घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाई और उस शो की विरानी फैमिली के कई मेंबर्स भारत के हर घर में छा गए थे. उन मेंबर्स में एक करन विरानी भी थे जो उस दौर में बहुत लोकप्रिय थे और इस किरदार को एक्टर हितेन तेजवानी ने निभाया था. अब जबकि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' आने वाला है, तब हितेन से पूछा गया कि क्या ये नया सीरियल 'अनुपमा' की टीआरपी को मात दे सकता है ?टेली मसाला को हाल ही में हितेन तेजवानी ने एक इंटरव्यू दिया. इसमें उनसे पूछा गया कि उनका शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 आने वाला है, लेकिन इन दिनों अनुपमा का बोलबाला है तो उनके शो का अनुपमा पर क्या असर पड़ेगा ? 'अनुपमा' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की तुलाना पर भी हितेन ने खुलकर जवाब दिया. हितेन तेजवानी ने बिना अनुपमा सीरियल का नाम लिए अपने शो को लेकर क्या-क्या कहा, आइए जानते हैं.

'अनुपमा' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में कोई तुलना है ?

इंटरव्यू में हितेन तेजवानी ने कहा, 'अब हम आ रहे हैं, हमें आने तो दीजिए. फिर बाद में आप लोग ही डिसाइड करेंगे कौन क्या है. हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले. जो चीज अच्छी है, अच्छी है, जो अच्छी नहीं है, आप मालिक हो, आपको पता है, सबको पता है. फैंस हैं, सब वो ही डिसाइड करते हैं, उन्हें जो चीज पसंद आती है वो यूं पसंद आती है, नहीं आती वो तुरंत बता देते हैं. आज कल की ऑडियंस क्लियर है इस मामले में. हम लोग किसी को नीचा दिखाने या कुछ नीचे करने के लिए नहीं आ रहे हैं. मुझे यकीन है मेकर्स भी चाहते थे एकता मैम भी कि कुछ लाए और आज की टाइम की बातें कर पाएं.'

कब से शुरू हो रहा 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ?

29 जुलाई से 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' शुरू हो रहा है. स्मृति ईरानी एक बार फिर तुलसी विरानी के रोल में नजर आएंगी, वहीं अमर उपाध्याय ने शुरुआती मिहिर विरानी का रोल प्ले किया था और इस बार तुलसी के मिहिर भी वही बनेंगे. वहीं हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान समेत कई पुराने किरदार भी इस शो का हिस्सा होंगे. इसके साथ ही कुछ नए चेहरे भी आप इस नये शो में देख पाएंगे. क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के प्रोमोज आ चुके हैं और फैंस को अब बस इस शो के टेलीकास्ट होने का इंतजार है.

51 साल की वो एक्ट्रेस, जिसके कहने पर दीपिका पादुकोण को मिली पहली फिल्म

9 नवंबर 2007ज्ये वो तारीख है जब आज के समय की सबसे बेहतरीन बॉलीवुड अदाकारा मानी जाने वाली दीपिका पादुकोण ने अपने कदम हिंदी सिनेमा में रखे थे. 'ओम शांति ओम' उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें एक्ट्रेस ने शाहरुख खान के साथ काम किया था. पहली ही फिल्म से दीपिका बॉलीवुड में छा गईं थीं. हालांकि आप ये नहीं जानते होंगे कि एक्ट्रेस को अपनी डेब्यू फिल्म कैसे मिली थी ?बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने से पहले दीपिका पादुकोण बैकग्राउंड मॉडल हुआ करती थीं. तब उन्हें मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के दोस्त और डिजाइनर वेन्डेल रोड्रिक्स भी जानते थे. जब ओम शांति ओम के मेकर्स अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे, तब मलाइका ने वेन्डेल रोड्रिक्स को ये बात बताई. उन्होंने दीपिका के नाम की सिफारिश की थी.

मलाइका की सिफारिश, दीपिका का हुआ डेब्यू

ओम शांति ओम का डायरेक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने किया था. फराह की मलाइका से भी अच्छी दस्ती है. फराह ने मलाइका से कहा था कि वो अपनी फिल्म के लिए शाहरुख खान के अपोजिट किसी नई लड़की की तलाश में है. इसके लिए मलाइका ने वेन्डेल रोड्रिक्स से संपर्क किया.डिजाइनर वेन्डेल रोड्रिक्स, दीपिका पादुकोण को जानते थे और उन्होंने फिर दीपिका का नाम सुझाया. वेन्डेल ने एक इंटरव्यू में बताया था , मैंने लैक्मे फैशन वीक का कलेक्शन दिखाया और ये दीपिका के लिए गेम चेंजर साबित हुआ. इसके बाद दीपिका को फिल्म के लिए शाहरुख खान के अपोजिट कास्ट कर लिया गया. फिल्म हिट साबित हुई. फिर एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

तलाकशुदा लाइफ जी रही हैं 51 साल की मलाइका

जिस मलाइका अरोड़ा की सिफारिश पर दीपिका को पहली फिल्म मिली थी वो मलाइका अब तलाकशुदा लाइफ जी रही हैं. 51 साल की हो चुकीं एक्ट्रेस ने साल 1998 में अभिनेता अरबाज खान से शादी की थी. हालांकि 19 साल बाद दोनों साल 2017 में तलाक लेकर अलग हो गए थे. तलाक के बाद मलाइका ने अभिनेता अर्जुन कपूर को डेट किया था. दोनों करीब 6 साल तक एक दूसरे के साथ रहे. इसके बाद उनका साल 2024 में ब्रेअकप हो गया था. एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो हाल ही में डांस रियलिटी शो 'हिप हॉप इंडिया सीजन 2' में बतौर जज नजर आई थीं.

Kingdom का ट्रेलर देख एक्साइटेड हो गईं

रश्मिका मंदाना

विजय देवरकोंडा की जमकर की तारीफ

सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के तमाम फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंगडम' के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं. इसे हिंदी में 'साम्राज्य' के नाम से रिलीज किया जा रहा है. ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फिल्म की काफी चर्चा हो रही है. रश्मिका मंदाना का भी एक पोस्ट सामने आया है.'साम्राज्य' (किंगडम) का ट्रेलर देखने के बाद रश्मिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया और लिखा, "Wohhhooo!क्या शानदार ट्रेलर है. मजा आ गया. इस कूल ट्रेलर को देखने के बाद फिल्म के लिए और चार दिन का इंतजार करना पड़ेगा. ये सही नहीं है. विजय दवरकोंडा मैं आपसे कहती रहती हूं कि आप सच में कुछ अलग हो.

विजय की तारीफ में ये भी बात भी कही

विजय की तारीफ में रश्मिका ने आगे ये भी लिखा, काश मैं अपने क्राफ्ट को इतने अच्छे से सीख लूं कि जितनी अच्छी एक्टिंग आप करते हो, मैं उसक 50 प्रतिशत कर पाऊं. आप कुछ अलग ही हो. रश्मिका ने 'साम्राज्य' (किंगडम) के डायरेक्टर गौतम तिन्नानुरी और म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर की भी तारीफ की है.

गौतम और अनिरुद्ध रविचंदर के लिए क्या लिखा ?

उन्होंने लिखा, गौतम और अनिरुद्ध आप दोनों जीनियस हो. बिल्कुल जीनियस. आप लोगों ने जो फिल्म बनाई है वो देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती हूं. इसमें विजय के साथ एक्ट्रेस भाग्यश्री बोरसे नजर आने वाली हैं. रश्मिका ने उनके लिए कहा, ऑल द बेस्ट क्यूटी. आपको 31ह्यह्ल को थिएटर में देखने के लिए इंतजार कर रही हूं.

पूर्व सीपीएस अनिता वर्मा ने सांसद अनुराग सिंह द्वारा राहुल के ऊपर दिए गए बयान पर किया पलटवार

दिव्य दिल्ली: समित कुमार (हमीरपुर)

हमीरपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सीपीएस अनिता वर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा राहुल गांधी के ऊपर दिए गए बयान पर पलट बार किया है। और साथ ही थुनाग में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को काले झंडे दिखाने को लेकर भी उन्होंने इस घटना को निंदनीय करार दिया है। और हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता इस आपदा के दौरान भी राजनीति कर रही है। हमीरपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सीपीएस अनिता वर्मा जब पहलगाम का बड़ा हादसा हुआ था जो बड़ा दर्द दायक है। भारत के लिए बड़ा संगीन मामला है। जिस पर भारत ने भी कार्रवाई की थी उसके बारे में बार-बार जितने विपक्ष के नेता थे।बार-बार चाह रहे थे कि हाउस बुलाया जाए और उसमें इस पर बातचीत की जाए। विपक्ष के नेता विपक्ष के सांसद होने के नाते बात को उठाया गया। इसका स्पष्टीकरण सत्ता में बैठी है जो सरकार उसको करना चाहिए। उसको उसकी सच्चाई बतानी चाहिए। इसलिए विपक्ष कुछ बातों को बार-बार उठा रहा है। बात राहुल गांधी पर थोप रहे हैं। कि वह पाकिस्तान के साथ है। यह कभी भी नहीं हो सकता है। एक पार्टी कभी भी अपने दुश्मन पार्टी से मिले हैं। यह कभी नहीं हो सकता। इस बयान पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वही अनीता वर्मा ने कहा कि दो साल में चुनाव आने वाले हैं प्रदेश में यह आपदा पहले कुल्लू में भी आई थी लेकिन अब मंडी में ज्यादा आई है। अच्छी बातों पर उन्हें सरकार का साथ देना चाहिए। सबसे अधिक नुकसान वाली जगह पर थुनाग में राजस्व मंत्री जा रहे थे। वहां पर सारी जमीन बह गई है तो आपको जमीन कहां पर दी जा सकती है। लोगों का क्या नुकसान हुआ है लेकिन वहां पर भी राजनीति की गई। जिसका नुकसान हुआ वह तो अपने नुकसान की समस्या नहीं उठा सके। लेकिन वहां पर राजनीतिक नेता थे जो काले झंडे लेकर सरकार खिलाफ बात छोड़ना चाह रहे थे। उन्होंने बात कि कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए। कॉलेज के संरक्षित स्थल पर निर्माण को लेकर राजस्व मंत्री गए थे। लेकिन वहां पर जो घटना घटी यह शोभा नहीं देती। भाजपा के जो सांसद और नेता जो दिल्ली जाकर मिले हैं

केवल योजनाएं बनाने तक ही सीमित नहीं, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करें

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी के दो दिवसीय दौरे के दौरान सोमवार शाम को सर्किट हाउस सभागार में प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए आजमगढ़ एवं वाराणसी मंडल के जन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों से उनके विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियों, जन अपेक्षाओं एवं विकासपरक कार्यों की प्राथमिकताओं के विषय में एक-एक कर व्यक्तिगत रूप से चर्चा की। बैठक का उद्देश्य मात्र योजनाओं की समीक्षा ही नहीं बल्कि जनोपयोगी, दूरवर्ती क्षेत्र का प्राथमिकता के आधार पर विकास सुनिश्चित करना था। संबंधित जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्यों की विधानसभावार चर्चा की।

न्यूज फ्लैश

बंजर भूमि पर किसान लगाए औषधीय पौधे , बढ़ेगी आए - विपन गुलेरिया

दिव्य दिल्ली: विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर औषधीय पौधे किसानों के लिए आज के दौर मे कितने लाभदायक साबित हो सकते हैं वहाँ जहाँ खासकर उन स्थानों पर भूमि बंजर या फिर कम उपजाऊ होती है' अक्सर कम बंजर भूमि किसानों के लिए यह जाती एल समस्या बनती है' अब इस समस्या को दूर करने के लिए औषधीय पौधो का उपयोग कर सकते हैं ' किसानों के लिए बेहतर मुनाफा देने का एक जरिया बन सकता हैं' बड़ी बात यह है कि इसमें खेती की लागत बहुत कम होती है दवा का छिड़काव आदि नहीं करना पड़ता है ' बचत भी काफी अच्छी मात्रा में होती है' इन सभी बातों को लेकर जिला कांगडा. के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जाच्छ (नूरपुर)की सह निदेशन एवं वैज्ञानिक डां विपन गुलेरिया ने औषधीय पौधों की खेती करने की सलाह देते हुए वताया कि मौसम भी अब पौधे लगाने के अनुकूल है ' क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जाच्छ (नूरपुर)की सह निदेशन डां विपन गुलेरिया ने कहा कि औषधीय पौधों की खेती? आमदनी बढ़ाने के लिए मददगार होते हैं गुलेरिया का कहना है कि हम लोग औषधीय पौधों की और सगंधीय पौधों की खेती को प्रमोट कर रहे हैं हम ज्यादातर किसान भाइयों के लिए औषधीय पौधों की खेती करें' उन्होंने आंबला , तुलसी, नीम, एलोवेरा, अश्वगंधा, गिलोय, ब्राह्मी, शतावरी, अदरक, हल्दी, और मेथी "हरड़" (ल्रं१ं) और "बेहड़ा" (ईंाँ) आदि ओषधिय पौधे लगाने की सलाह दी ' क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जाच्छ (नूरपुर)की सह निदेशन डां विपन गुलेरिया ने वताया कि आमदनी बढ़ाने के लिए यह औषधीय पौधे मददगार होते हैं. क्योंकि औषधीय पौधे सामान्य तौर पर जंगलों में पाए जाते हैं. हमारे जंगल सारे नष्ट हो चुके हैं. ऐसे में जंगल में उगने वाले पौधों की खेती कैसे करें इसको लेकर किसान भाइयों को गाइडेंस दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि जंगली औषधीय पौधे से वो अच्छे किस्म के पौधे तैयार करते है जिससे अच्छी पैदावार हो रही है उन्होंने कहा कि संस्थान में यह पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जाते है ' सह निदेशक डां विपन गुलेरिया ने बताया की अभी तक प्रदेश में औषधीय पौधों की मंडी नहीं है मगर प्रदेश के बाहर अच्छे दाम मिलते है ।

राजस्व मंत्री की भाजपा महामंत्री ने लगाई जमकर क्लास

दिव्य दिल्ली: शशि भूषण (धर्मशाला)

भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य कांग्रेस सरकार पर खूब हमला बोला त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार में एक ऐसे बेलगाम मंत्री है, जिनकी हरकतों व बदजुबानी को पिछले अढ़ाई साल से जनता झेल रहे हैं उन्होंने कहा कि मंत्री की जुबान पर जल्द लगाम न लगाने पर राज्य भर में बड़े आंदोलन किए जाएंगे त्रिलोक कपूर ने कहा कि राजस्व व बागबानी का जिम्मा संभाल रहे है, लेकिन हर मोर्चे पर उक्त मंत्री फेल रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित मंडी के सराज में भयंकर तबाही हुई है, जिससे समस्त जनता वहां की जूझ रही है, 30 से अधिक अपने लोगों को हमने खो दिया, जबकि मंत्री सचिवालय में बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री को कहते हैं कि अपने पांवों में कांटे चुभने की बेतुकी बात करते हैं साथ ही मंत्री पीड़ित लोगों में से 65 पर एफआईआर दर्ज कर-के ओर दुखी किया जा रहा है उन्होंने सीएम से मांग रखी है कि इस एफआईआर को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए जबकि ऐसा न करने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा। कपूर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हर आपदा के स्थान में पहुंचकर जरूरी मदद उपलब्ध करवाने के लिए डटे हुए हैं ।

जूनियर दिवाज ऑफ इंडिया सीजन 2 ने रैडिसन ब्लू में मचाया धमाल

दिव्य दिल्ली : दिल्ली के रैडिसन ब्लू, पश्चिम विहार में A2B प्रोडक्शन और HDS फिल्म्स द्वारा आयोजित जूनियर दिवाज ऑफ इंडिया सीजन 2 का आयोजन बेहद शानदार रहा। यह कार्यक्रम बच्चों की स्टाइल, आत्मविश्वास और प्रतिभा का उत्सव बन गया। इस मौके पर कई सेलिब्रिटीज, मॉम ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और 20 से अधिक बच्चों के ब्रांड्स – जैस Kidbest, Eak Star, Merry Little Things, Fashion Awas, Spothunt, Lakmé आदि ने भाग लेकर इस आयोजन को और खास बना दिया। लड़कियों की श्रेणी में कियांशी, साईशा, त्रिशा और आध्या विजेता बनीं, जबकि लड़कों की श्रेणी में समीर, लविश और माधव ने जीत हासिल की। सभी प्रतिभागियों ने अपनी कला और आत्मविश्वास से दर्शकों और निर्णायकों का दिल जीत लिया।

कार्यक्रम के दौरान A2B प्रोडक्शन ने अपने नए ब्रांड एंबेसडर्स सुविक्षा, जिशान और अशनूर की भी घोषणा की, जो भविष्य में ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे। जूनियर दिवाज ऑफ इंडिया बच्चों के लिए एक बेहतरीन मंच है जहाँ वे अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और ग्लैमर की दुनिया में अपना पहला कदम रख सकते हैं।

स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट चिंतपूर्णी द्वारा मंडी के आपदा पीड़ित परिवारों के लिए राहत सामग्री का द्वितीय चरण प्रेषित

दिव्य दिल्ली: राम प्रकाश (ऊना)
स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट चिंतपूर्णी द्वारा मंडी जिले में हाल ही की आपदा से प्रभावित बच्चों और परिवारों के लिए रविवार को राहत सामग्री का दूसरा चरण भेजा गया। इस चरण में 145 बच्चों के लिए 1500 नोटबुक, पेन, पेंसिल तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, जरूरतमंद परिवारों को राशन, आवश्यक वस्तुएं एवं अन्य राहत सामग्री भी प्रदान की गई। इस सेवा कार्य में ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष एवं सचिव श्री अभिनव शर्मा, तथा श्री विशाल, श्री जतिन, श्री केशव सहित ट्रस्ट के अन्य समर्पित कार्यकर्ताओं ने सक्रिय योगदान दिया

जवाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भोल खास के वार्ड नं दो मैं दिनदहाड़े चोरी होने का मामला

दिव्य दिल्ली: राजेश कतनौरिया (जबाली)

जवाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भोल खास के वार्ड नं दो मैं दिनदहाड़े चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है प्रात जानकारी के अनुसार भोल खास पंचायत के पूर्व प्रधान सृषटा देवी के घर दिन दहाड़े चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है सृषटा देवी ने बताया कि हमारे दो मकान है एक थोड़ी दूरी पर है लगभग साढ़े ग्यारह बजे पानी भरने के बाद में ताला लगाकर दूसरे मकान की ओर चली गई और मेरा पोता जब स्कूल से आधी छुट्टी के समय घर आया तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ और अंदर देखा तो समान इधर उधर बिखरा हुआ था पूर्व प्रधान सृषटा देवी ने बताया कि पोते ने आवाज लगाई और कहा कि दादी जी हमारे घर का किसी ने ताला तोड़ दिया सृषटा देवी ने बताया कि जब मैं घर पहुंची तो देखा दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर समान इधर-उधर बिखरा हुआ था गोदरेज की अलमारियों के ताले व लाकर तोड़ दिये गये थे अलमारी के अंदर रखे हुए सोने व चांदी के गहने व नकदी लगभग 10 हजार रुपये चुराकर ले गये हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार की ईको टूरिज्म सोसाइटी द्वारा आपदा राहत कोष में 50 लाख का योगदान

दिव्य दिल्ली: शशि भूषण (धर्मशाला)

हिमाचल प्रदेश सरकार की ईको टूरिज्म सोसाइटी ने आज एक सराहनीय सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए राज्य आपदा राहत कोष में ?50 लाख का योगदान दिया है। यह सहायता प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उदार और समयानुकूल योगदान के लिए ईको टूरिज्म सोसाइटी के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ह्लऐसे योगदान समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचायक हैं। आपदा की घड़ी में इस प्रकार की एकजुटता और करुणा से पीड़ितों को त्वरित राहत एवं पुनर्वास में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ईको टूरिज्म सोसाइटी जैसे संस्थानों का सहयोग अन्य संस्थाओं और नागरिकों को भी आगे आकर सहयोग देने के लिए प्रेरित करता है।इस अवसर पर ईको टूरिज्म सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यकारी समिति सदस्य श्री संजीव गांधी ने कहा, ह्लहम न केवल राज्य में ईको टूरिज्म को स्थानीय समुदाय की भागीदारी से प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि समाज की सेवा और लोगों के समग्र कल्याण के लिए भी पूरी तरह समर्पित हैं। संकट की इस घड़ी में हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं।ह्व ईको टूरिज्म सोसाइटी का यह योगदान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता को दशार्ता है, बल्कि मानवीय सेवा में भी उनके समर्पण को उजागर करता है

सोलन सब्जी मंडी में पहुंची सेब की अर्ली वैरायटी 33 करोड़ का हो चुका है

दिव्य दिल्ली: अमरप्रीत सिंह (सोलन)

सोलन सब्जी मंडी में पहुंची सेब की अर्ली वैरायटी 33 करोड़ का हो चुका है व्यापार आधुनिक मंडियो में शुमार सोलन की फल एवं सब्जी मंडी में निचले क्षेत्रों का सेब पहुंचना शुरू हो गया है। सोलन जिला के दाडलाघाट, देवठी, सिरमौर के कुछ क्षेत्र सहित मंडी जिला के क्षेत्र सहित करसोग ,ि ठयोग व कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र का सेब फल मंडी सोलन में पहुंच रहा है। अभी तक सोलन मंडी में 2 लाख 73 हजार सेबी की पेटी पहुंच चुकी है। जिसका व्यापार 33 करोड़ का हो चुका है। एपीएमसी सोलन के सचिव अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि सोलन सब्जी मंडी में निचले क्षेत्रों का अर्ली व्यारटी का सेब अब बडी मात्रा में पहुंचने लगा उन्होंने कहा कि इस सीजन में अभी तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से दो लाख 73 हजार सेबी पेटियां से 33 करोड़ का व्यापार हो चुका है। उन्होंने कहा कि सेब के दाम भी अच्छे है। व पिछले वर्ष के मुताबिक इस बार सेब अधिक मात्रा में पहुंचने का अनुमान उन्होंने बताया।

प्रदेश में 6 महीनों से संगठन का न होना चिंता का विषय: कृष्ण भारद्वाज

दिव्य दिल्ली: प्रेम स्वरूप शर्मा (नगरोटा सूरियां)

ज्वाली ब्लॉक कांग्रेस मीडिया प्रभारी कृष्ण भारद्वाज ने अपनी ही पार्टी को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में 6 महीनों से संगठन का न होना चिंता का विषय है तथा संगठन के न होने के कारण सरकार तक जनता की आवाज न पहुंचने के कारण सरकार प्रदेश की आम जनता से कट चुकी है। बात तो सरकार व संगठन के तालमेल के बारे में की जाती थी परन्तु इतने लंबे समय से संगठन का न होने तालमेल को बेमेल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के समय पर निर्णय न लेने के कारण ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता हताश हैं तथा उन पर दूसरी पार्टी वालों ने उनके साथ आने के लिए डोरे डालने अन्दर खाते शुरू कर दिए हैं। पार्टी कार्यकताओं का अपनी ही पार्टी के सत्ता में होने के बावजूद कोई काम नहीं हो रहा है। जिसके परिणाम पार्टी को निकट भविष्य में भुगतने पड़ सकते है। भारद्वाज ने प्रदेश हित, राष्ट्र हित, सरकार हित तथा पार्टी हित में प्रदेश में जल्द कांग्रेस संगठन को बनाकर कार्यकताओं के कामों पर विशेष ध्यान देने की सरकार व पार्टी हाईकमान से मांग की है

नाकाबन्दी तोड़कर भागी गाड़ी को विभागीय टीम ने रैहन के समीप किया काबू

दिव्य दिल्ली: राजेश कतनौरिया (भरमाड़)

उपमंडल जवाली के अधीन सोमवार देर रात्रि वन विभाग द्वारा समलाना में की गई नाकाबन्दी के दौरान एक गाड़ी नाका तोड़कर भाग निकली जिसे विभागीय टीम ने रैहन के समीप काबू कर लिया। सेंट्रो गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें खैर के छिलके पाए गए जिससे लग रहा था कि गाड़ी में खैर को बेचकर कहीं से आए हैं। सेंट्रो कार ने रैहन में तीन-चार अन्य वाहनों को टक्कर मारकर उनका काफी नुकसान किया है। वन विभाग ने कार चालक अमित कुमार निवासी ढसोली को पकड़कर उसको मुचलके पर छोड़ दिया है तथा कार को अपने कब्जे में ले लिया है। आरओ जवाली आशीष कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम ने समलाना में नाकाबन्दी की हुई थी कि एक सेंट्रो कार को रुकने का इशारा किया तो वह वहां से भाग निकला। पीछा करते हुए कार को चालक सहित रैहन में दबोच लिया गया। वन विभाग ने अमित कुमार निवासी ढसोली को पकड़कर मामला दर्ज कर मुचलके पर छोड़ दिया है तथा कार को अपने कब्जे में ले लिया है। कार की नंबर प्लेट पर जो नंबर लिखा है वो किसी अन्य गाड़ी का लग रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अमित कुमार को डीएफओ नूरपुर की अदालत में पेश किया जाएगा

जिला पुलिस नूरपुर को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता

दिव्य दिल्ली: विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर प्रदेश में पुलिस जिला नुरपूर द्वारा नशे के खिलाफ चलाये गये अभियान के अन्तर्गत दिनांक 27.10.24 को पुलिस थाना डमटाल के अन्तर्गत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई थी ।जिसमें कंवलजीत सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह निवासी अर्जुन नगर डा०) छ्याटा, गली न0 3, तहसील व जिला अमृतसर, पंजाब के कब्जे से 262 ग्राम चिट्टा बरामद करने मे सफलता प्राप्त की थी। जिस पर उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना डमटाल में अभियोग संख्या 127 / 24 दिनांक 27.10.24 अधीन धारा 21 एन डी एंड पी एस एक्ट के अधीन पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इस अभियोग में गिरफ्तार आरोपी से की गई पूछताछ व तथ्यों की जांच के द्धारा यह पाया गया कि इस अभियोग में अन्य लोग भी शामिल हैं। जिनकी तलाश जिला पुलिस नूरपुर द्वारा विभिन्न-2 स्थानों पर की जा रही थी। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा पेशेवर ढंग से कार्यवाही करते हुए दिनांक- 08.04.25 को इस अभियान में शामिल एक अन्य आरोपी राजेश कुमार पुत्र लक्ष्मण दास निवासी अर्जुन नगर डा० छ्याटा ट्ट तहसील व जिला अमृतसर को जिला कांगड़ा के धर्मशाला से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी गिरफ्तार आरोपी राजेश कुमार पुत्र लक्ष्मण दास से कड़ी पूछताछ अमल में लाई गई ।जिसने पुलिस को एक जांच के दौरान बताया कि अवैध चिट्टे की तस्करी का सारा कारोबार दुबई से चल रहा है। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा गुप्त रूप से इस अभियोग की आगामी जांच जारी रखी गई तथा जांच में पाए गये तथ्यों के आधार पर दिनांक 13.04.25 को नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी में शामिल एक अन्य आरोपी राज कुमार उर्फ सेठी पुत्र दौलत राम निवासी भदरोया तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। इस अभियोग में पूछताछ व तथ्यों की जांच के आधार पर दिनांक 15.04.25 को एक अन्य आरोपी लखविंदर कोहली पुत्र हरबंस ताल, निवासी अदसेवा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को भदरोया से गिरफ्तार करने सफलता प्राप्त की।

बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से की लूट

कानपुर। महाराजपुर थाना क्षेत्र के खाटू खेड़ा गांव में दो बाइक बाइक सवार छह बदमाशों ने सरार्फा व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए उनकी स्कूटी, मोबाइल और बैग छीन लिया। बैग में ज्वेलरी और नकदी मिलाकर दो से ढाई लाख रुपये का सामान था। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पीड़ित की स्कूटी लावारिश अवस्था में खड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी से मिली तहरीर के आधार पर मामले की पड़ताल में जुट गई है। यह जानकारी सोमवार को डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने दी।

चकेरी के लाल बंगला इलाके में रहने वाले सरार्फा व्यापारी अनिल कुमार वर्मा की नर्वल थाना क्षेत्र के टौंस में यादव ज्वेलर्स के नाम से दुकान है।

बताया कि जब वह शाम को दुकान बंद कर वापस लौट रहे थे। तो उनके पास एक बैग था। जिसमें में आठ से नौ ग्राम सोना दो किलो चांदी और 40 हजार रुपये नकद था।

दुकान से करीब पांच किलोमीटर दूर बारादरी घाटू खेड़ा के पास अचानक दो बाईकों पर छह बदमाश पीछा करते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर ही गिर पड़े। इसके बाद बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी स्कूटी और बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित किसी को सूचना न कर सके।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397